स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–21, अंक–10, आश्विन–कार्तिक 2070, अक्टूबर 2013

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा–4

आज का भारत चीन की हर चुनौती के लिए तैयार है। चाहे वह सामरिक हो या फिर आर्थिक। बाजार से संबंधित हो या फिर तकनीक से संबंधित। भले ही केंद्र की सरकार चीन के सामने सीना चौड़ा कर खड़े होने में झिझके, पर राष्ट्रवादी ताकतें चीन की हर चुनौती देने के लिए तैयार हैं।

कवर पेज

अ नु क्र म

आवरण कथा : स्वदेशी जागरण मंच का चीन को ललकार
– विक्रम उपाध्याय /4

अर्थव्यवस्था :
अमरीकी अर्थव्यवस्था की रुपए पर छाया
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /7

स्वास्थ्यः
महंगा इलाज – सस्ती होती जान
– सुभाषचन्द्र कुशवाहा /9

बाजारवादः
बेईमानी है जीरो परसेंट ईएमआई
– आलोक पुराणिक /11

विश्लेषणः
राजनीतिक गलियारों से. . .
– जवाहरलाल कौल /14

विमर्शः
गाँधी को भूल गयी सरकार
– निरंकार सिंह /16

पर्यावरणः अवैध खनन द्वारा नदियों से खिलवाड़
– मुकुल श्रीवास्तव /20

अभिमतः चीन की चिंता – हमारी उम्मीद
– जयंतीलाल भंडारी /27

भ्रष्टाचारः
घोटालेबाजी की ये भी कोई सजा है?
– डॉ. वेदप्रताप वैदिक /29

सुरक्षाः
परमाणु दायित्व कानून से खिलवाड़
– अरविन्द जयतिलक /30

धरोहरः
भूलना मत कि एक माँ गंगा भी है
– अरुण तिवारी /32

अस्तित्वः इंटरनेट की दुनिया में हमारी हिन्दी. . .?
– उमेश चतुर्वेदी /34

पाठकनामा/2, समाचार परिक्रमा/22, रपट/35

पाठकनामा

कब मिलेगी महंगाई से मुक्ति

देष में महंगाई रूपी दानव दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। आम नागरिक इस महंगाई रूपी दानव से परेषान हो गया है लेकिन सरकार है महंगाई को थामने की जगह महंगाई को बढ़ाने का काम कर रही है। कभी पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि तो कभी डीजल–सीएनजी के दामों की वजह से आए दिन सब्जी से लेकर स्कूल फीस भी बढ़ती जा रही है। अब ऐसा लगता है कि महंगाई से त्रस्त जनता को किसी तरह की कोई राहत मिलने वाली नहीं है। पिछले नौ साल में जनता सिर्फ आलू, प्याज, आटा और जरूरी चीजों की महंगाई से ही परेशान नहीं है बल्कि ऐसे कई खर्च हैं जो हाल में चार गुना तक बढ़ गए हैं। सरकारी आंकड़े भी यही बताते हैं कि 2004 से लेकर अब तक स्कूल फीस में 432 प्रतिशत, मूंग, उड़द, अरहर की दाल में 129 से लेकर 190 प्रतिशत, आलू पर 158 प्रतिशत और टमाटर की कीमत पर 129 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। इसके अलावा डॉक्टर की फीस में 129 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर सरकार कहती है कि महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। सोचने वाली बात है। जनता परेशान सरकार मस्त। आने वाले चुनावी दिनों में जनता को वर्तमान सरकार को सबक सिखाना ही चाहिए।

– महेन्द्र कुमार, उत्तम नगर, दिल्ली

देशभक्त और भ्रष्टाचार खत्म करने वाली पार्टी को दे वोट

मैं स्वदेशी पत्रिका नियमित रूप से पढ़ता हूँ। पत्रिका में प्रकाशित लेख देशहित और देश की समस्याओं को लगातार उजागर करते रहते है। पत्रिका के द्वारा ही मैं अपने मित्रों में देशहित और समस्याओं को उजागर करता रहता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि वर्तमान में केन्द्र में बैठी सरकार देशहित की जगह अमरीकी हित ज्यादा देखती है। अब एक बार फिर से जनता के हाथ में सरकार चुनने का मौका आ गया है। एक तरफ से देखा जाए तो चुनाव का सेमीफाइनल शुरू हो गया है। विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। जनता बढ़ती महंगाई, घोटालों, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार और सरकारी बाबूओं से पीड़ित है। चुनावी बिगुल में जनता ही जर्नादन है और जनता के हाथ में चाबी है। समय आ गया है कि उसे ऐसी सरकार चुनना चाहिए जो देशहित और भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लेती हो।

– केसर मेहरा, नौएडा

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

अमरीका में बजट बिल नामंजूर हुआ यह सब अमरीकी लोकतंत्र का दोष है। अमरीका टूटा नहीं है उसे बस एक मियादी दौरा पड़ा है।

– सिमोन जेनकिन्स ब्रिटिश पत्रकार

आज हमें महात्मा गांधी की तस्वीर को दीवार से हटा कर अपने दिल में वापस बसा लेनी चाहिए। हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी बातों से सीखना चाहिए।

– शेखर कपूर

कैग के ताजा आंकड़ों से साफ हो गया है कि भाजपा शासित राज्यों में जहां कुपोषण तेजी से घटा है वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में यह सरकार की प्राथमिकता सूची में ही नहीं शामिल है।

– रविशंकर प्रसाद

आज देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व सीमा सुरक्षा बड़ा सवाल बन गया है। केन्द्र की मौजूदा व्यवस्था विफल रही है। इस कारण आम लोगों को इस व्यवस्था में अब भरोसा नहीं रहा है। देश को आज ऐसे नायक की जरूरत है जो कुशल, जिम्मेदार और व्यवस्था परिवर्तन करने का क्षमता रखता हो।

– मोहन भागवत (आरएसएस)

अपना देष कमजोर होता है तो सभी प्रकार की विदेषी पूंजी उड़न छू हो जाएगी। अगर देष तरक्की करता है तो तमाम प्रकार के देषों के लोग एवं कंपनियां भारत के साथ जुड़कर अपना भविष्य उज्ज्वल करना चाहेंगे।

– डॉ. अश्विनी महाजन

संपादकीय

भारती या भारत से वालमार्ट की विदाई

वालमार्ट ने भारती के साथ अपना व्यापारिक संबध खत्म कर दिए हैं। इसके साथ यह भी घोषणा कर दी है कि आने वाले कुछ महीनों तक वह खुदरा व्यापार के क्षेत्र में अपने मेगा स्टोर खोलने की योजना को ठप कर दिया है। वैसे सिर्फ वालमार्ट ही क्यों दुनिया की लगभग सभी खुदरा व्यापार क्षेत्र की कंपनियां भारत से दूरी बनाए हुई हैं। इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की मंजूरी को देश की अर्थव्यवस्था और खासकर किसानों के लिए वरदान बताने वाली केंद्र की सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर इस क्षेत्र में विदेशी निवेश के प्रस्ताव गए कहां? खुदरा क्षेत्र में सिंगल ब्रांड वाले विदेशी निवेश के प्रस्ताव आने तो दूर अब इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है, क्योंकि अमरीकी ही नहीं, फ्रांस और जर्मनी की कंपनियां भी इस मामले में भारत से दूर रहने का ही फैसला किया है। जनवरी 2012 में भारत में सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार के क्षेत्र में 51 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी तब से क्राकरी, फैशन और स्पोर्ट्स सामान के अलावा कोई बड़ा प्रस्ताव नहीं आया। वैसे वालमार्ट ने भारती के साथ संबंध तोड़ने के जो कारण बताए हैं, उस पर यकीन करें तो यह माना जाना चाहिए कि वालमार्ट को भारत सरकार की यह शर्त चुभ रही है कि उसे खुदरा क्षेत्र में निवेश के लिए कम से कम 30 फीसदी माल की खरीददारी भारतीय निर्माताओं और किसानों से करनी पड़ेगी। वालमार्ट के अनुसार उसके लिए इस शर्त का पालन मुश्किल है। इसके अलावा भारत में भ्रष्टाचार, बिजली की कमी, आर्थिक सुधार की धीमी गति और राजनीतिक अनिश्चितता भी वालमार्ट के इस फैसले की वजह हैं। क्या अमरिकी प्रशासन के जरिए भारत के खुदरा व्यापार क्षेत्र में विदेशी निवेश की मंजूरी दिलाने के पीछे दिन रात एक करने वाली इस बहुराष्ट्रीय कंपनी को सचमुंच भारत से मोह भंग हो गया है। या इसके पीछे कुछ और भी कारण है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी निवेशकों को भी लगने लगा है कि अगले चुनाव में कांग्रेस की हार तय है और अंदरखाने में जो भी तय हुआ है उसे लागू होनें में अब खतरा है। दुनिया भर की सरकारों को हिलाने वाले विदेशी निवेशक यह मानते हैं कि भारत में आने वाले दिनों में यदि भाजपा या एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनी तो खुदरा व्यापार के क्षेत्र पर कब्जा जमाने का सपना देखने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भाजपा ने संसद में यह ऐलान किया है कि यदि उसकी सरकार केंद्र में बनी तो खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की मंजूरी वापस ले ली जाएगी। वालमार्ट ने अपने कदम पीछे खींचने के लिए भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाया है, जबकि हकीकत यह है कि यह बहुराष्ट्रीय कंपनी खुद ही भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरी है। भारती के साथ इसका करार और इसका निवेश पहले से संदेह के घेरे में हैं। कहा जा रहा है कि वर्ष 2007 में वालमार्ट ने भारती को 10 करोड़ डॉलर का जो ब्याज मुक्त कर्ज दिया था, वह वास्तव में पिछले दरवाजे से खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश ही था। कई भारतीय विभाग इसकी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा यह खबर भी है कि भारत में ख़ुदरा व्यापार के क्षेत्र में विदेशी निवेश की मंजूरी दिलाने के लिए वालमार्ट ने यहां एक बड़ी राशि घूस के रूप में भी दी थी। इसकी भी जांच की मांग उठ रही है। यहीं नहीं दुनिया के कई देशों की सरकारों को अपनी शर्त मनवाने के लिए वालमार्ट ने भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया । ब्राजील, चीन और भारत में रिश्वत देने की घटना वालमार्ट के गले पड़ गईं है। वालमार्ट ने खुद स्वीकार किया है कि उसकी विदेशी सब्सिडयरी के खिलाफ विभिन्न जांचों के कारण उसे लगभग 15 करोड़ डॉलर के नुकशान की आशंका है। खुद अमरीकी प्रशासन वालमार्ट के भ्रष्टाचारों की जांच कर रहा है। वालमार्ट पूरी दुनिया में अपने अनैतिक व्यापार के लिए बदनाम कंपनी है। इसलिए उसका यह तर्क कि भारत में भ्रष्टाचार के कारण वह खुदरा व्यापार के क्षेत्र में आने का फैसला बदल रही है, महज एक बहाना है। हालांकि अभी सिर्फ भारती के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को वालमार्ट ने तोड़ा है। खबर यह भी है कि थोक क्षेत्र के अपने ब्रांड कैश एंड कैरी का व्यवसाय वालमार्ट जारी रखेगी। और इसके लिए अपना कोई अलग ब्रांड या कोई नया व्यावसायिक साझीदार ढूंढेगी। वालमार्ट समेत सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के बारे में अब सिर्फ प्रतीक्षा व सर्तकता की नीति अपना रही हैं।

स्वदेशी जागरण मंच का चीन को ललकार

सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर मुँहतोड़ जवाब देंगे

आज का भारत चीन की हर चुनौती के लिए तैयार है। चाहे वह सामरिक हो या फिर आर्थिक। बाजार से संबंधित हो या फिर तकनीक से संबंधित। भले ही केंद्र की सरकार चीन के सामने सीना चौड़ा कर खड़े होने में झिझके, पर राष्ट्रवादी ताकतें चीन की हर चुनौती देने के लिए तैयार हैं।

चीनी सामानों की होलिका जलाते हुए स्वदेशी जागरण मंच (जमशेदपुर) के कार्यकर्ता

■ विक्रम उपाध्याय

चीन का आक्रामक रवैया अब भारतीयों के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लगातार हमारी सीमाओं पर उसका अतिक्रमण और उसके बावजूद हमारी सरकार का चीन के सामने समर्पण एक राष्ट्र के नाते हमारे लिए घोर अपमानजनक स्थिति है। एक संप्रभु और स्वाभिमानी देश के नाते हमारा परम कर्त्तव्य बनता है कि हम चीन की इस नव साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का मुँहतोड़ जवाब दें। स्वदेशी जागरण मंच ने देश की ओर से चीन की चुनौती का जवाब देने का बीड़ा उठाया है। मंच के कार्यर्त्ताओं ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश समेत लगभग पूरे देश में चीन की असलियत उजागर करने के लिए जनता को जागरूक बनाने, चीनी सामानों के उपयोग से बचने के लिए प्रेरित करने और सरकार द्वारा चीन के सामने हथियार डालने पर लानत–मलानत करने और सबसे अधिक जोर चीनी चुनौती के लिए खुद को तैयार करने का एक सघन अभियान चलाया है।

मंच ने देश की ओर से चीन को यह कड़ा संदेश दिया है कि वह भारत की भूमि और भारत के बाजार पर अपने कब्जे के अभियान से बाज आए नहीं तो भारतीय इस बार 1962 के युद्ध का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत इस समय कहीं से भी चीन की घुड़की में नहीं आने वाला। अब यह इतिहास की बात है कि 1962 के युद्ध में समय चीन ने हमारी 30 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया और नेहरू की सरकार कुछ नहीं कर पाई। आज का भारत चीन की हर चुनौती के लिए तैयार है। चाहे वह सामरिक हो या फिर आर्थिक। बाजार से संबंधित हो या फिर तकनीक से संबंधित। भले ही केंद्र की सरकार चीन के सामने सीना चौड़ा कर खड़े होने में झिझके, पर राष्ट्रवादी ताकतें चीन की हर चुनौती देने के लिए तैयार हैं।

पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व बनाने का सपना देख रहे चीन के लिए दरअसल भारत ही सबसे अधिक खतरा है। इसलिए चीन की साम्यवादी सरकार हमारे प्रति ज्यादा आक्रामक और क्रूर है। कभी अरुणाचल में घुसपैठ तो कभी लद्दाख में। कभी मैकमोहन रेखा के पास शिविर का निर्माण तो कभी पाकिस्तान की सीमा के सहारे भारत तक आसान पहुंच बनाने के लिए हाईवे का निर्माण, चीन की पूरी कोशिश है कि वह भारत को कहीं न कहीं उलझाए रखे ताकि वह अपनी नव–साम्राज्यवादी नीति आसानी से लागू कर सके। चीन की नजर न सिर्फ भारत पर है, बल्कि वह म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं का भी अतिक्रमण कर रहा है। पाकिस्तान ने तो कई सामरिक महत्व के ठिकाने चीन को सौंप दिए हैं। चीनी शासकों को मालूम है कि इन देशों में से भारत ही है जिसे कठोर चुनौती मिल सकती है। न सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी।

सच तो यह है कि चीन खुद से डरा हुआ है। विकास का जो मॉडल चीन ने पिछले 20 वर्ष में खड़ा किया है, उसके बने रहने को लेकर पुरी दुनिया संशकित है। कहा जा रहा है कि चीन का आर्थिक बुलबुला कभी भी फट सकता है। चीनी शासक अपने सैन्य अभियान के जरिए भारत जैसे देश को दबा धमका कर आर्थिक मोर्चे पर पीछे रखने के मंसूबे पाले हुए हैं।

लगभग आठ फीसदी की दर से आर्थिक विकास कर रहे चीन के सामने चुनौती ही यही है कि वह अगले 20 वर्ष तक किस तरह इस विकास दर को स्थिर बनाए रख सकता है। मौजूदा समय में चीन की पूरी अर्थव्यवस्था उच्च पूंजी लागत पर निर्भर है। कहा जा रहा है कि चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए लगभग 4 खरब डॉलर का निवेश हर वर्ष प्राप्त करना होगा। जो मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल में बेहद कठिन कार्य है। चीन की दूसरी बड़ी समस्या है उसका कमजोर मानव–संसाधन। एक परिवार एक बच्चे की नीति के कारण चीन में काम–काज करने वाले लोगों का प्रतिशत तेजी से नीचे आ रहा है। कहा जा रहा है कि अगले 15 वर्ष में चीन की 60 फीसदी से अधिक आबादी बूढ़ी हो जाएगी और भारत की 70 फीसदी आबादी युवाओं की होगी। चीन को भारत से सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या के मोर्चे पर ही मिलने वाली है। ताजा आंकड़े के अनुसार चीन के प्राथमिक विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या में औसत 18 फीसदी की गिरावट आ रही है, जबकि भारत में प्राथमिक विद्यालयों में जाने वालों बच्चों की जनसंख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है। यद्यपि पूरी दुनिया की 40 फीसदी से अधिक आबादी

मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल जी "चीन की चुनौती एवं समाधान" विषय पर बोलते हुए (जबलपुर, मध्यप्रदेश)

चीन और भारत में ही रहती है, पर कार्यशील आबादी का प्रतिशत चीन के मुकाबले भारत में काफी अधिक है। पढ़े लिखे और पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ने वाले लोगों में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। यही कारण है कि चीन का विकास मॉडल तीव्र औद्योगिकीकरण और ढ़ांचागत विकास पर आधारित है भारत का विकास मॉडल में सेवा उद्योग सबसे ऊपर है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत का डंका बजता है, पर चीन का प्रदर्शन इस क्षेत्र में नगण्य है।

''चीनी आक्रमण और केन्द्र सरकार की निष्क्रिय भूमिका'' पर जनसभा स्वदेशी जागरण मंच (प. बंगाल के कार्यकर्ता)

आज चीन भले ही पूंजी निवेश को आकर्षित करने में भारत से मिलों आगे हैं। चीन ने विनिर्माण के क्षेत्र में खुद को दुनिया के एक बड़े हब के रूप में विकसित कर लिया है। आसान शर्तों पर ढांचागत सुविधाएं मिलने और उदार कर व्यवस्था के कारण चीन लगभग सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चीन का जीडीपी भारत के कुल जीडीपी से पांच गुणा से भी अधिक हो गया है। पर चीन में काम करने वाली कंपनियों के लिए सबसे बड़ी समस्या वहां काम करने वाले मजूदरों को लेकर है। अधिकतर चीनी नागरिक अपनी भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं बोल पाते। साम्यवादी सरकार के लगातार शासन में होने और वहां लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को तोप के गोले से कुचल देने की प्रवृत्ति के कारण चीनी जनता में घोर असंतोष है। इसलिए यह माना जा रहा है कि चीन में कभी भी गृहयुद्ध की स्थिति आ सकती है। इसलिए बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन के अलावा भी अपने निर्माण की इकाइयां खोलना चाहती है। उनके लिए भारत सबसे आदर्श जगह हो सकता है। इस तथ्य को चीन भली–भांति जानता है। इसलिए वहां की सरकार भारत को न सिर्फ एक अस्थिर राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहती है, बल्कि यह संदेश भी देना चाहती है कि भारत की सरकार पर जब चाहे चीन नकेल डाल सकता है।

सरकार निक्कमी हो तो जनता को जागरूक होना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच यही आव्हान करता है कि सीमा पर जवान और देश में आम आदमी मिलकर चीन की चुनौती का जवाब दे।

चीन भारत को सीमा विवाद में भी उलझाएं रखना चाहता है, ताकि वह भारत की तरक्की और उसकी पहचान को बाधित करता रहे। इस काम में चीन की सेना उसकी सरकार का पूरा साथ देती है। चीन न सिर्फ अपनी ओर से बल्कि नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार को भी भारत के विरुद्ध उकसाने में लगा रहता है। कभी भारत के साथ अपनी पहचान बनाए रखने के लिए लालायित नेपाल को चीन अब साम्यवादियों के प्रभुत्व के सहारे अपनी ओर खींचने और भारत के खिलाफ माहौल तैयार करने में पूरी मदद प्रदान कर रहा है।

भारत सरकार यह सब जानती है। लेकिन कमजोर नेतृत्व और मजबूत इच्छा शक्ति के अभाव के कारण चीन को माकूल जवाब देश नहीं दे पा रहा है। बल्कि उलटे चीन आए दिन भारत को धमकी दे रहा है। अपनी सीमा की चौकसी करते भारतीय जवानों का चीन मजाक उड़ा रहा है। सरकार संसद में यह बयान देती है कि चीन ने कोई अतिक्रमण नहीं किया, जबकि मीडिया के जरिए यह कई बार देखने में आया कि चीन हमारी सीमा का आए दिन उलंघन करता है। यह संभव नहीं कि हम लंबे समय तक हाथ पर हाथ धर के बैठे। यदि सरकार निक्कमी हो तो जनता को जागरूक होना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच यही आव्हान करता है कि सीमा पर जवान और देश में आम आदमी मिलकर चीन की चुनौती का जवाब दे। ❑

अमरीकी अर्थव्यवस्था की रुपए पर छाया

आश्चर्य की बात है कि इन दुरूह बुनियादी परिस्थितियों के बावजूद स्टिमुलस जारी रखने के निर्णय अमरीका और भारत दोनों के ही शेयर बाजारों में उछाल आया है। मैं इसे निवेशकों की अल्पदर्शिता का परिणाम मानता हूं। उन्हें मात्र यह दिख रहा है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर न्यून रखने से उनके लिये ऋण लेना आसान बना रहेगा और अमरीकी अर्थव्यवस्था फिलहाल मंदी की चपेट में नहीं आयेगी। उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि भारी स्टिमुलस के बावजूद अमरीकी अर्थव्यवस्था मन्द पड़ी हुयी है। उन्हें यह भी नहीं दिख रहा है कि अमरीकी उपभोक्ता ऋण से दबते जा रहे हैं। ऋण की अदायगी करने के लिये उनके पास रोजगार नहीं हैं।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

अमरीकी केन्द्रीय बैंक ने स्टिमुलस पैकेज जारी रखने का निर्णय लिया है। 2008 के बाद से केन्द्रीय बैंक ने ब्याज दरों को शून्य पर टिका रखा है। इससे अमरीकी नागरिकों के लिये ऋण लेकर मकान खरीदना आसान हो गया है। नये मकान को बनाने में रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं और स्टील तथा सीमेंट की मांग उत्पन्न हो रही है। इससे अमरीकी अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 2 प्रतिशत प्रति वर्ष पर बनी हुयी है।

लेकिन दो समस्यायें हैं। एक यह कि अमरीका ऋण के बोझ से दबता जा रहा है। शीघ्र ही उपभोक्ताओं की ऋण की अदायगी करनी होगी। लेकिन इस ऋण की अदायगी के लिये रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। दूसरी समस्या है कि बढ़ते ऋण के बोझ के बावजूद अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ रही है। केन्द्रीय बैंक ने कुछ माह पहले विकास दर का पूर्वानुमान 2.3 प्रतिशत का लगाया था। इसे अब घटाकर 2.0 प्रतिशत कर दिया गया है। जाहिर होता है कि अर्थव्यवस्था दबाव में है।

स्टिमुलस पैकेज का निवेशकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अमरीका के ब्याज दर न्यून होने के कारण वे अपनी रकम को अमरीका में निवेश नहीं करना चाहते हैं। बल्कि अमरीका में शून्यप्राय दर पर ऋण लेकर वे विदेशों में निवेश करके लाभ कमाना चाहते हैं। यूं समझें कि अमरीकी केन्द्रिय बैंक द्वारा जारी किये गये स्टिमुलस पैकेज का अंतिम लाभ भारत जैसे उन देशों को होता है जहां निवेशक पूंजी लगाते हैं। केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष बेन बेरनानके ने बीते समय संकेत दिये थे कि स्टिमुलस में कटौती की जा सकती है। इसका परिणाम होता कि अमरीका में ब्याज दर में वृद्धि होती। निवेशकों के लिये भारत से पैसा निकालकर अमरीका में निवेश करना लाभप्रद हो जाता। इस संभावना के चलते निवेशकों ने भारत से पूंजी निकाला था और रुपया टूटा था। अब स्टिमुलस के जारी रहने से पुनः निवेशक भारत की ओर रुख कर रहे हैं और रुपया उठने लगा है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति अनिश्चित जान पड़ती है। एक ओर विकास दर 2 प्रतिशत पर टिकी हुयी है। दूसरी ओर इसमें गिरावट आने का अनुमान है। प्रश्न है कि अमरीकी अर्थव्यवस्था में दिख रहा सुधार टिकाऊ होगा या नहीं?

मेरा आकलन है कि अमरीकी अर्थव्यवस्था में दिख रहा सुधार टिकाऊ नहीं होगा। यह सुधार ऋण पर आधारित है। जैसे दुकानदार लोन लेकर आलीशान शोरूम बना लें और उसमें चार सेल्समैन नियुक्त कर दे तो बेशक रोजगार उत्पन्न होंगे लेकिन मूल बात तो बिक्री की है। यदि शोरूम से पर्याप्त बिक्री और आय होती है तो ऋण की आदायगी हो पायेगी

और सेल्समैन के रोजगार टिकाऊ होंगे। बिक्री और आय के अभाव में दुकानदार लोन का रिपेमेंट नहीं कर पायेगा और शीघ्र ही दुकानदार का दिवाला निकल जायेगा और सेल्समैन की नौकरी समाप्त हो जायेगी। ऐसी ही स्थिति अमरीका की है।

वर्ष 2008 एवं 2012 के बीच अमरीकी सरकार के द्वारा लिये गये ऋण में 5,300 अरब डालर की वृद्धि हुयी। इसके सामने अमरीका की आय में मात्र 1,500 अरब डालर की वृद्धि हुयी। यूं समझिये कि एक डालर ऋण लेकर अमरीकी सरकार देश की आय में मात्र 28 सेन्ट की वृद्धि हासिल कर पायी। यह भी स्वीकार होता यदि ऋण का उपयोग निवेश के लिए किया गया होता। तब भविष्य की आय की संभावना बनती। जैसे दुकानदार ऋण लेकर शोरूम बनाता है तो बिक्री धीरे–धीरे बढ़ती। परन्तु अमरीकी सरकार ने धन का उपयोग चालू खर्चों को पोषित करने के लिये किया न कि निवेश के लिये। रिसर्च, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं में किये जाने वाले निवेश में कटौती हुयी है। इसलिये ऋण के उपयोग से नई आय उत्पन्न नहीं हो रही है। ऋण पर ब्याज चढ़ता रहा है और अमरीका के पुनः संकटग्रस्त होने की संभावना बन रही है।

दुर्भाग्यवश निवेशकों द्वारा रोजगार में देखी जा रही वृद्धि को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और बढ़ते ऋण को नजरंदाज किया जा रहा है। जैसे एथलीट स्टेरायड लेकर तेज दौड़े तो इसे उसकी टिकाऊ क्षमता नहीं समझना चाहिये। इसी प्रकार ऋण के बल पर बन रहे रोजगार को टिकाऊ नहीं समझना चाहिये।

वर्तमान में रोजगार में जो वृद्धि दिख रही है उसमें भी संदेह हैं। नये रोजगार पार्ट टाइम एवं न्यून वेतन वाले उत्पन्न हो रहे हैं। चार फुल टाइम सेल्समैन के स्थान पर आठ पार्ट टाइम सेल्समैन रख लें तो रोजगार उत्पन्न होते दिखेंगे जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होगा। दूसरा संदेह है कि भारी संख्या में लोग हताश हो चुके हैं और उन्होंने रोजगार ढूंढ़ना ही बन्द कर दिया है।

केन्द्रीय बैंक द्वारा स्टिमुलस जारी रखने के निर्णय के बाद अध्यक्ष श्री बेरनानके ने कहा है कि बेरोजगारी दर में गिरावट नये रोजगारों के सृजन के कारण नहीं हुयी है। लोगों ने रोजगार ढूंढ़ना बन्द कर दिया है इसलिये आंकड़ों में बेरोजगारी कम दिख रही है।

अमरीकी सरकार ने धन का उपयोग चालू खर्चों को पोषित करने के लिये किया न कि निवेश के लिए. . . . इसलिये ऋण के उपयोग से नई आय उत्पन्न नहीं हो रही है। ऋण पर ब्याज चढ़ता रहा है और अमरीका के पुनः संकटग्रस्त होने की संभावना बन रही है।

इनकी गिनती बेरोजगारों में नहीं होती है जबकि ये पूर्णतया बेरोजगार हैं। वर्तमान उत्साह का दूसरा आधार पूर्वानुमान है। 43 प्रमुख अर्थशास्त्रियों के सर्वे के हवाले बताया गया कि अगले वर्ष के मध्य में विकास दर 3 प्रतिशत पर पहुंच जायेगी जो कि वर्तमान में एक से दो प्रतिशत के बीच मंडरा रही है। यह आकलन भी मुख्यतः बढ़ते रोजगार पर आधारित है जो कि स्वयं संदेह के घेरे में है।

मेरे अनुमान में अमरीका में वर्तमान में दिख रहा उछाल वास्तव में आने वाले संकट का द्योतक है जैसे दिया बुझने के पहले धधकता है। वर्तमान सुधार पूर्णतया ऋण पर आधारित है। जैसे डिस्काउण्ट देकर दुकानदार माल बेच लेता है उसी प्रकार ब्याज दर न्यून रखकर केन्द्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को चलाया है। डिस्काउण्ट देने की सार्थकता तबाही है जब बाद में ऊंचे दाम पर माल को बेचा जा सके। परन्तु अमरीका ऐसा कर सकेगा इसकी संभावना कम ही है।

मूलरूप से अमरीका की प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति का ह्रास हो रहा है। स्टिमुलस समाप्त होने के साथ–साथ ब्याज दर में वृद्धि होगी और संकट पुनः आना शुरू हो जाएगा।

आश्चर्य की बात है कि इन दुरूह बुनियादी परिस्थितियों के बावजूद स्टिमुलस जारी रखने के निर्णय अमरीका और भारत दोनों के ही शेयर बाजारों में उछाल आया है। मैं इसे निवेशकों की अल्पदर्शिता का परिणाम मानता हूं। उन्हें मात्र यह दिख रहा है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर न्यून रखने से उनके लिये ऋण लेना आसान बना रहेगा और अमरीकी अर्थव्यवस्था फिलहाल मंदी की चपेट में नहीं आयेगी। उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि भारी स्टिमुलस के बावजूद अमरीकी अर्थव्यवस्था मन्द पड़ी हुयी है। उन्हें यह भी नहीं दिख रहा है कि अमरीकी उपभोक्ता ऋण से दबते जा रहे हैं। ऋण की अदायगी करने के लिये उनके पास रोजगार नहीं हैं। मैं बाजार के इस उछाल से सहमत नहीं हूं।

मेरा मानना है कि अमरीकी अर्थव्यवस्था अन्दर से खोखली होती जा रही है और सुधार कृत्रिम है। जैसे कैंसर के मरीज को पेन किलर दे दिया जाए तो वह कुछ समय के लिये हंसने बोलने लगता है। ❑

महंगा इलाज - सस्ती होती जान

उदारीकरण की नीतियों पर तेजी से अमल करती सरकार की सारी की सारी नीतियां ही दोहरी व्यवस्था लागू कर रही हैं। गरीबों के लिए जहां 16 रुपये दैनिक मजदूरी में भरण–पोषण की बात की जाती है, वहीं अमीरों के लिए एक वक्त का भोजन सात हजार रुपये का होता है! ऐसे में समाज में कुंठा, आक्रोश या विघटन पनपना स्वाभाविक है। क्या हमारी सरकार और देश के नौकरशाह मौजूदा परिदृश्य पर मनन करेंगे? सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि वहां हजारों–लाखों मरीज आते हैं।

■ **सुभाषचंद्र कुशवाहा**

इस लोकतांत्रिक देश के हर वर्ग के लिए एक संविधान, समान कानून और विधान होते हुए भी सब कुछ असमान और भिन्न है। सामर्थ्यवानों के लिए कानून, प्रशासन और विधायिका जितने सुलभ और हितपोषक हैं, उतने ही आम आदमी के लिए दूभर और जलालत भरे! चाहे वह दोहरी शिक्षा व्यवस्था हो या बिना योग्य डॉक्टरों के सरकारी अस्पतालों का इलाज। जिसकी जेब में पैसा है, उसके लिए देश में पंचसितारा निजी अस्पताल मौजूद हैं, और जिनकी इतनी हैसियत नहीं, उनके लिए सरकारी अस्पताल। यानी जितनी औकात, वैसी सुविधा!

आज डेंगू, इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, टायफाइड आदि के मरीजों से सरकारी अस्पताल भरे पड़े हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ही बिना योग्य डॉक्टर के और संविदा पर तैनात पैरा मेडिकल स्टाफ के सहारे एक हजार के लगभग इंसेफेलाइटिस मरीजों का इलाज हो रहा है। नतीजतन, अब तक यहां दो सौ से अधिक मरीज अपनी जान गंवा भी चुके हैं, लेकिन शासन मौन है।

दिल्ली में डेंगू मरीजों का आंकड़ा अब तक दो हजार पार कर चुका है। पिछले साल जनवरी से दिसम्बर तक 2093 डेंगू के मामले सामने आए। लेकिन सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। डेंगू के मरीजों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं की कमी का खुलासा कई अखबारों में प्रकाशित भी हो चुका है लेकिन सरकारी तंत्र कोई न कोई बहाना ढूढ़ लेता है। जहां मच्छरों को पनपने से पहले रोकने का काम प्रत्येक निगम को करना चाहिए था, वही निगम चालान काटना व कानूनी नोटिस जारी करना की कार्यवाही में लगा रहता है।

दरअसल, निजी अस्पतालों के महंगे इलाज का सामर्थ्य गरीबों में नहीं है। ऐसे में झाड़–फूंक, भभूत और ताबीज में ही वे अपने इलाज की राह खोजते हैं। नीतियां बनाने वाले कर्णधारों को भी लगने लगा है कि इस देश की चिकित्सा व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट सकती। लिहाजा उन्होंने भी अपना इलाज विदेशों में करवाने की व्यवस्था कर ली है। दुखद है कि जिन नौकरशाही–नीतियों के चलते पूरे देश की सरकारी चिकित्सा व्यवस्था लकवाग्रस्त हो गई है, उन नीतियों का पोषण करने वालों को दंडित करने के बजाय उपकृत किया जा रहा है। अगर

नीतियां बनाने वाले कर्णधारों को भी लगने लगा है कि इस देश की चिकित्सा व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट सकती। लिहाजा उन्होंने भी अपना इलाज विदेशों में करवाने की व्यवस्था कर ली है। दुखद है कि जिन नौकरशाही–नीतियों के चलते पूरे देश की सरकारी चिकित्सा व्यवस्था लकवाग्रस्त हो गई है, उन नीतियों का पोषण करने वालों को दंडित करने के बजाय उपकृत किया जा रहा है।

ऐसा नहीं है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए विदेशी अस्पतालों में इलाज कराने की व्यवस्था कैसे कर दी गई? इतना ही नहीं, आपातकालीन चिकित्सा के लिए हेलिकॉप्टर से राज्य के बाहर ले जाने की सुविधा भी उन्हें मुहैया कराई गई है।

विषमता देखिए कि बाबू और लिपिक ही नहीं, दूसरे संवर्ग के अधिकारियों को भी ऐसी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब इससे बेहतर हमारे देश के समतावादी संविधान की और क्या विशेषता हो सकती है!

चिकित्सा की बेहतर नीति बनाने वाले प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने स्वतः मान लिया है कि देश में मेडिकल पढ़ाई का स्तर इतना गिर चुका है कि न तो योग्य और उच्च दक्षता वाले डॉक्टर पैदा हो रहे हैं और न हमारे चिकित्सालयों में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो रही है। ऐसे में वे इलाज के लिए विदेशों का रुख करने लगे हैं। लेकिन उन हजारों–करोड़ों आम लोगों का क्या, जिनकी हैसियत आज भी सरकारी अस्पतालों तक ही जाने की है। क्या देश के दूसरे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा हासिल करने का हक नहीं है?

एक दृष्टांत देखिए। पूर्वांचल में 1976 से इंसेफेलाइटिस की महामारी फैली हुई है, जबकि इस देश के प्रशासनिक अधिकारियों ने 2006 में जाकर इस क्षेत्र में टीकाकरण के बारे में सोचा, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हो पाया है। यानी इंसेफेलाइटिस के प्रकोप से मरते मरीजों की 30 वर्ष बाद सुधि तो ली, लेकिन वह भी अधूरी। और जब बात खुद पर आती है, तो वे तुरंत इलाज कराने विदेश भाग जाते हैं।

सवाल यह भी है कि यह 'चिकित्सा पर्यटन' की सुविधा ऐसे समय हासिल की गई है, जब डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपये की क्रय शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही है और हम पर विदेशी कर्ज पहाड़–सा बढ़ता जा रहा है।

बहरहाल, मौजूदा परिदृश्य देश में एकसमान विधान का एहसास नहीं कराता। क्या आम लोगों को बेहतर इलाज का अधिकार नहीं? देखा जाए, तो उदारीकरण की नीतियों पर तेजी से अमल करती सरकार की सारी की सारी नीतियां ही दोहरी व्यवस्था लागू कर रही हैं। गरीबों के लिए जहां 16 रुपये दैनिक मजदूरी में भरण–पोषण की बात की जाती है, वहीं अमीरों के लिए एक वक्त का भोजन सात हजार रुपये का होता है! ऐसे में समाज में कुंठा, आक्रोश या विघटन पनपना स्वाभाविक है। क्या हमारी सरकार और देश के नौकरशाह मौजूदा परिदृश्य पर मनन करेंगे? सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि वहां हजारों–लाखों मरीज आते हैं। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

बेईमानी है जीरो परसेंट ईएमआई

मोबाइल फोनों पर मुफ्त ईएमआई की स्कीम को हाल के दौर की सफल मार्केटिंग स्कीम के तौर पर चिन्हित किया जा रहा था। पर इस सफलता में ग्राहकों के अज्ञान की भूमिका बहुत ज्यादा थी। रिजर्व बैंक ने इस अज्ञान जनित मार्केटिंग सफलता पर रोक लगाई है, तो इसे उचित ही माना जाना चाहिए मंदी से त्रस्त उद्योग यह मांग नहीं कर सकते हैं कि मंदी में हमें ग्राहकों की जेब काट लेने की इजाजत दे दी जाए। मंदी से निपटने का रास्ता बेईमानी से नहीं, रचनात्मकता से होकर जाता है।

■ आलोक पुराणिक

मंदी के मारे उद्योग जगत और खास तौर पर मोबाइल कंपनियों के विक्रेताओं ने रिजर्व बैंक के उस नोटिफिकेशन पर परेशानी जताई है, जिसमें जीरो परसेंट ईएमआई की घोषणा वाली स्कीमों को बंद करने का आदेश दिया गया है। होता यूं था कि जीरो परसेंट ईएमआई की घोषणाओं, विज्ञापनों में तमाम कंपनियां कुछ इस तरह की बातें करती नजर आती थीं मानो मुफ्त में ही यह रियायत ग्राहकों को दी जा रही है। वित्तीय निरक्षरता के मारे ग्राहकों के पास यह देखने की फुरसत नहीं कि मुफ्त ईएमआई का मतलब क्या है। मुफ्त तो दरअसल कुछ होता ही नहीं। पर ग्राहकों के अज्ञान के चलते कंपनियां जमकर रकम बटोर रही थीं, बिक्री बढ़ा रही थीं। बिक्री बढ़ाना हर कंपनी का हक है। पर ग्राहकों के अज्ञान का फायदा उठाना कारोबार नहीं, बेईमानी की श्रेणी में आता है।

हाल में मोबाइल फोन तक बेचने के लिए जीरो परसेंट ईएमआई की घोषणाएं हुई और सेल चल निकली। अब रिजर्व बैंक का डंडा फ्री ईएमआई पर चला है, तो बिजनेस चैनलों और आर्थिक अखबारों में कारोबारी शिकायत करते दिख रहे हैं कि मंदी के मौसम में ऐसी मार ठीक नहीं है। पर सच यह है कि जीरो ईएमआई का कंसेप्ट ही गलत है। रिजर्व बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि जीरो परसेंट ईएमआई या जीरो परसेंट लोन के नाम पर हो यह रहा है कि ब्याज को प्रोसेसिंग फीस के नाम से वसूला जा रहा है। कुछ बैंक तो अपने लोन सेल्समैन को दिए जाने वाले कमीशन को भी ग्राहकों से वसूल रहे हैं। यह सब करते हुए बैंक कह यही रहे थे कि जीरो परसेंट इंटरेस्ट, जीरो ईएमआई। ऐसे–ऐसे इश्तिहार आने लगे, जिनमें बताया जाने लगा कि बंदा लंच टाइम में दफ्तर से बाहर गया और नया मोबाइल खरीद लाया हजारों का, जीरो ईएमआई पर। क्रेडिट कार्ड के जरिये मोबाइल खरीदा, मुफ्त ईएमआई पर। ब्याज को प्रोसेसिंग फीस के नाम पर देने के बाद भी ग्राहक को लगता है कि वह तो ब्याज–मुक्त आइटम ले आया है।

सच्चाई यह है कि रुपया तो ग्राहक की जेब से जा रहा है, चाहे ब्याज की शक्ल में लो या प्रोसेसिंग फीस की शक्ल में। चोट तो आखिर कस्टमर को ही पड़नी है। महंगी संपत्तियों की खरीद के लिए शुरू हुआ ईएमआई का सिलसिला मकान और कार से आगे अब मोबाइल फोन तक आ गया। हजारों के मोबाइल फोन खरीदने की हैसियत नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, किश्तों पर लीजिए। पर इसमें आपत्तिजनक यह हुआ कि जिसे मुफ्त ईएमआई कहकर बेचा गया, वह मुफ्त था नहीं।

रिजर्व बैंक ने अपने नोटिफिकेशन के जरिए एक अनुचित मार्केटिंग तकनीक पर प्रहार किया है। जो मंदी के मौसम में बहुत गहरा लग रहा है। यूं रिजर्व बैंक के इस कदम से अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह कम होगा, कर्ज कम दिए जाएंगे, कई वस्तुओं की मांग में एक हद तक कमी आएगी और महंगाई पर एक हद तक नियंत्रण लगेगा। मांग कम होने से कीमतें नीचे आती हैं। रिजर्व बैंक की महंगाई रोकने की नीति के लिए यह घटी हुई मांग मददगार साबित हो सकती है।

इस कदम से ग्राहकों को भी फायदा होने का आसार हैं, जो मुफ्त के चक्कर में बहुत चीजें खरीदे ले रहे थे और जो अंततः उन्हें महंगी ही साबित हो रही थीं। धुआंधार विज्ञापन दिखाकर पब्लिक के मन में इच्छाएं जगाना, फिर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उधार का रास्ता बताना और फिर यह भी बताना कि ये उधार तो मुफ्त है, ब्याज मुक्त है, ये मार्केटिंग रणनीति हाल के दिनों में कई आइटम के विक्रेताओं में बहुत पापुलर हो रही थी। इससे ग्राहकों का भला चाहे न हो रहा हो, पर बेचने वालों का भला तो हो ही रहा था। दरअसल, ईएमआई के कंसेप्ट का बेजा इस्तेमाल भारत में मार्केटिंग करने वालों ने किया है। इसमें मुफ्त, ब्याजमुक्त ईएमआई जैसे कंसेप्ट जोड़कर तो ईएमआई के कंसेप्ट को लगभग बेईमान ही बना दिया गया। ईएमआई का इक्वेटेड मंथली इंस्टालमेंट्स या किश्त का कंसेप्ट मूलतः उन उत्पादों के लिए था जो महंगे होते हैं और जिन पर खर्च करना एक बार में कोई आम ग्राहक अफोर्ड नहीं कर सकता। मकान, कार इस श्रेणी में आते हैं। ईएमआई का बुनियादी उद्देश्य यह रहता था कि एक महंगी संपत्ति को भी आर्थिक तौर पर अपेक्षाकृत कमजोर ग्राहक के दायरे में ले आएं। बाद में तमाम आइटमों के लिए ईएमआई का प्रयोग किया गया।

विज्ञापन दिखाकर पब्लिक के मन में इच्छाएं जगाना, फिर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उधार का रास्ता बताना और फिर यह भी बताना कि ये उधार तो मुफ्त है, ब्याज मुक्त है, ये मार्केटिंग रणनीति हाल के दिनों में कई आइटम के विक्रेताओं में बहुत पापुलर हो रही थी। इससे ग्राहकों का भला चाहे न हो रहा हो, पर बेचने वालों का भला तो हो ही रहा था।

भारत में ही विदेशी पर्यटन के लिए ईएमआई का प्रयोग शुरू हुआ। कई ट्रेवल पैकेज कंपनियां कर्ज लेकर विदेशी पर्यटन का मौका देने लगीं। अभी घूम आइए, पांच साल तक सस्ती ईएमआई देते रहिए। पर इस तरह के ईएमआई पैकेज में साफ तौर पर दर्ज होता था कि इसमें ब्याज दर इतनी, प्रोसेसिंग फीस इतनी। बाद में कंपनियों की मार्केटिंग बहुत स्मार्ट हुई तो ब्याज का हिस्सा कम किया गया, प्रोसेसिंग फीस का हिस्सा बढ़ता गया। ब्याज को ब्याज की तरह न वसूल करके उसे प्रोसेसिंग फीस की तरह वसूलना शुरू हुआ। प्रोसेसिंग फीस को ग्राहक अनिवार्य तत्व मानकर उसे झेलने को तैयार हो जाता है। इस पर ज्यादा किचकिच नहीं होती।

पर सच्चाई यह है कि रुपया तो ग्राहक की जेब से जा रहा है, चाहे ब्याज की शक्ल में लो या प्रोसेसिंग फीस की शक्ल में। चोट तो आखिर कस्टमर को ही पड़नी है। महंगी संपत्तियों की खरीद के लिए शुरू हुआ ईएमआई का सिलसिला मकान और कार से आगे अब मोबाइल फोन तक आ गया। हजारों के मोबाइल फोन खरीदने की हैसियत नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, किश्तों पर लीजिए। पर इसमें आपत्तिजनक यह हुआ कि जिसे मुफ्त ईएमआई कहकर बेचा गया, वह मुफ्त था नहीं। मुफ्त का भ्रम जरूर हो सकता है। उसी भ्रम में कारोबारी माल बेचकर निकल लेते हैं। मंदी कमोबेश सब तरफ ही है। ऑटोमोबाइल कंपनियां भी मंदी से जूझ रही हैं और पिज्जा कंपनियां भी। पर मुफ्त ईएमआई के जरिए ग्राहकों को लुभाने के बजाए ये दूसरे रास्ते तलाश रही हैं।

एक पिज्जा कंपनी बुधवार को एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा मुफ्त देने का प्रस्ताव कर रही है, हालांकि मुफ्त यहां भी कुछ नहीं होगा। एक की कीमत देने पर दूसरा उसके साथ आएगा। पर एक के भाव में दो मिलने की मार्केटिंग रणनीति कारगर हो सकती है। इस रणनीति को रचनात्मक माना जा सकता है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति के आंकड़े

ब्याज को प्रोसेसिंग फीस के नाम पर देने के बाद भी ग्राहक को लगता है कि वह तो ब्याज–मुक्त आइटम ले आया है। रिजर्व बैंक ने अपने नोटिफिकेशन के जरिए एक अनुचित मार्केटिंग तकनीक पर प्रहार किया है। जो मंदी के मौसम में बहुत गहरा लग रहा है। यूं रिजर्व बैंक के इस कदम से अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह कम होगा, कर्ज कम दिए जाएंगे, कई वस्तुओं की मांग में एक हद तक कमी आएगी और महंगाई पर एक हद तक नियंत्रण लगेगा। रिजर्व बैंक की महंगाई रोकने की नीति के लिए यह घटी हुई मांग मददगार साबित हो सकती है।

बताते हैं कि अप्रैल–जून 2013 की अवधि में, अप्रैल–जून 2012 की अवधि के मुकाबले बिक्री में 5.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, पर मुनाफा 49 प्रतिशत बढ़ा इस अवधि में। इसका श्रेय मारुति कंपनी लागत कटौती और दूसरी परियोजनाओं को देती है। मारुति मंदी का इस्तेमाल अपनी क्षमता बढ़ाने में कर रही है। आगामी तीन वर्षों में यह अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसका फायदा आने वाले वक्त में कंपनी को मिलेगा। घरेलू बाजार में सुस्ती को देखकर कंपनी एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इन तरकीबों से मंदी को मात दी जा सकती है। और ऐसी तरकीबों से ही मंदी को मात दी जानी चाहिए।

मोबाइल की कीमतें सस्ती हो जाएं कि उन्हें कर्ज पर न लेना पड़े, ऐसी मार्केटिंग रणनीति बनाई जाए। या फिर महंगे मोबाइलों की तरफ सिर्फ प्रीमियम ग्राहकों को आकर्षित किया जाए।

बाजार में हर आइटम हर कस्टमर को बेचना भी बहुत अक्लमंद मार्केटिंग रणनीति नहीं है। मंदी के वक्त, संकट के वक्त समझदार और गैर–समझदार कारोबारियों का पता चलता है। समझदार कारोबारी मंदी में नए रास्ते खोजता है, गैर–समझदार कारोबारी घिसी–पिटी तकनीकों का इस्तेमाल करके उबरना चाहता है, और उसमें कई बार विफल होता है।

मोबाइल फोनों पर मुफ्त ईएमआई की स्कीम को हाल के दौर की सफल मार्केटिंग स्कीम के तौर पर चिन्हित किया जा रहा था। पर इस सफलता में ग्राहकों के अज्ञान की भूमिका बहुत ज्यादा थी। रिजर्व बैंक ने इस अज्ञान जनित मार्केटिंग सफलता पर रोक लगाई है, तो इसे उचित ही माना जाना चाहिए मंदी से त्रस्त उद्योग यह मांग नहीं कर सकते हैं कि मंदी में हमें ग्राहकों की जेब काट लेने की इजाजत दे दी जाए। मंदी से निपटने का रास्ता बेईमानी से नहीं, रचनात्मकता से होकर जाता है। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

राजनीतिक गलियारों से. .

चार राज्यों में इसी वर्ष विधान सभाओं के लिए मत डाले जाएंगे और नई सरकारें चुनी जाएगीं। इनमें से दो पर अभी कांग्रेस का अधिकार है तो दो पर भाजपा का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारें हैं और दिल्ली व राजस्थान में कांग्रेस की। रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री के नाते छवि ठीक बताई जाती है और दोनों के पास दिखाने के लिए कुछ उपलब्धियां भी हैं लेकिन दूसरी तरफ शीला दीक्षित और गहलौत भी खाली हाथ नहीं।

■ **जवाहरलाल कौल**

लोग इन्हें सेमीफाइनल कहते हैं लेकिन अगर इससे यह अर्थ निकाला जाए कि आने वाले चार विधानसभा चुनावों में हार–जीत पर ही लोकसभा चुनाव का दारोमदार टिका है तो सही नहीं होगा। आज भारतीय मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अंतर करना सीख चुका है। इस बात के अनेक उदाहरण हैं कि विधानसभा चुनावों में हार के बाद भी कोई दल लोकसभा में जीत दर्ज कर ले।

चुनावों का सेमीफाइनल किसी क्रिकेट हाकी या फुटबाल की तरह नहीं कि सेमीफाइनल में हार गए तो फाइनल से बाहर हो गए। यहां तो हारने और जीतने का बस इतना भर महत्व है कि जीतने वाले के लिए माहौल थोड़ा अनुकूल बन जाता है। इस चुनावी सेमीफाइनल में जो हारेंगे उन्हें भी फाइनल प्रतियोगिता में तो शामिल होना ही है।

चार राज्यों में इसी वर्ष विधान सभाओं के लिए मत डाले जाएंगे और नई सरकारें चुनी जाएगीं। इनमें से दो पर अभी कांग्रेस का अधिकार है तो दो पर भाजपा का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारें हैं और दिल्ली व राजस्थान में कांग्रेस की। रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री के नाते छवि ठीक बताई जाती है और दोनों के पास दिखाने के लिए कुछ उपलब्धियां भी हैं लेकिन दूसरी तरफ शीला दीक्षित और गहलौत भी खाली हाथ नहीं। वे भी सफलता के दावे कर सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत छवि को मानक मान लें तो चारों राज्यों में पुरानी सरकारें लौट आनी चाहिए। लेकिन चुनाव के मानक और भी हैं जो इस साधारण गणित को गड़बड़ा सकते हैं। मतदाता का उकता जाना उनमें से प्रधान है।

आर्थिक मामलों का हर राज्य के वोटरों पर असर पड़ना स्वाभाविक है लेकिन दिल्ली पिछले कई चुनावों में प्याज के मामले में कुछ अधिक संवेदनशील बन गई है। महंगाई देश के लिए बहुत जटिल समस्या बनी हुई है। आम आदमी इससे त्रस्त है और यह त्रास मतदात के गुस्से में बदल सकता है। इसमें एक सामान्य सब्जी यानी प्याज ने रहस्यमय ढंग से खाद्य वस्तुओं की तुलना में खास महत्व प्राप्त किया है। पिछले कुछ चुनावों का रुख बदलने में रोजमर्रा के उपयोग की इस छोटी सी सब्जी ने महत्वपूर्ण भमिका निभाई है।

एक सरकार को पांच साल झेलते–झेलते मतदाता उकता जाता है। इस तरह लोगों की ऊब का कारण केवल यह नहीं होता कि लोग बार–बार उन्हीं चेहरों को देखना पसंद नहीं करते अपितु यह भी है कि दस में से तीन चार मतदाता ही सरकार के काम से संतुष्ट होते हैं क्योंकि उनके अपने काम नहीं होते। मतदाता अधूरे वायदों का ठीकरा सरकार के सर फोड़ने के लिए आतुर होते हैं। कभी–कभी सरकार के किसी मंत्री या बड़े अधिकारी का नाम किसी बड़े घोटाले या दुष्कर्म से जुड़ जाता है जैसे अभी–अभी राजस्थान के एक पूर्व मंत्री दुष्कर्म के आरोप से घिर गए हैं। ऐसे कांड अक्सर गुड़ गोबर कर देते हैं और सरकार सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं। ऐसे स्थिति में मुख्यमंत्री अपनी छवि से किस हद तक मतदाता का ध्यान ऐसे विवादों से हटा पाते हैं, यह समय ही बताएगा। अंतिम मानक राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की छवि होती है।

हालांकि सामान्य स्थिति में इसका राज्य के बारे में सीमित असर होता है लेकिन असामान्य स्थितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व का असर व्यापक भी होता है। विचारणीय सवाल यह है कि क्या इन चार राज्यों के चुनाव नतीजे अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव का पूर्वानुमान होंगे? इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि अगर

दोनों दलों ने अपने राज्य बचा लिए तो अनुमान लगाना संभव नहीं होगा लेकिन अगर कांग्रेस राजस्थान और दिल्ली हार गई और भाजपा अपने दोनों राज्यों को बचा ले गई तो हवा का रुख महसूस किया जा सकता है।

हालांकि दिल्ली में किसी दल के विधानसभा चुनाव हारने से देश की संसद में उसकी हार तय नहीं होती और न ही दिल्ली विधानसभा की जीत संसदीय चुनावों में उसकी जीत का कोई आश्वासन है, फिर भी जिस पार्टी को दिल्ली राज्य के विधानसभा चुनावों में सफलता मिले, उसके पक्ष में 2014 के आम चुनाव में हवा बनने का अनुमान तो लगाया ही जा सकता है क्योंकि यह देश की राजधानी है। राष्ट्रव्यापी मुद्दों की हवा अमूमन यहीं से बहना शुरू होती है। इसीलिए दोनों प्रतिस्पर्धी दल इस राज्य को जीतने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस सत्तारूढ़ होने के कारण अधिक अनुकूल स्थिति में है क्योंकि उसे राज्य की विभिन्न योजनाओं और हाल में घोषित केंद्रीय योजनाओं का सीधा लाभ मिल जाता है। प्रत्यक्ष नकदी अनुदान जैसी योजनाओं का प्रभाव देश के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा, जिनमें सभी उस गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनके चुनावी रुझानों पर अक्सर रोजी–रोटी सम्बंधित सुविधाओं का प्रभाव पड़ सकता है।

दिल्ली में मैट्रो रेल को भी कांग्रेस अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है और इसका आंशिक असर पड़ भी सकता है लेकिन विपक्ष भी इस मामले पीछे नहीं। वह बिजली की दरों में तीस प्रतिशत की कटौती जैसे वायदे कर रहा है।

कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक मामलों का हर राज्य के वोटरों पर असर पड़ना स्वाभाविक है लेकिन दिल्ली पिछले कई चुनावों में प्याज के मामले में कुछ अधिक संवेदनशील बन गई है। महंगाई देश के लिए बहुत जटिल समस्या बनी हुई है। आम आदमी इससे त्रस्त है और यह त्रास मतदाता के गुस्से में बदल सकता है। इसमें एक सामान्य सब्जी यानी प्याज ने रहस्यमय ढंग से खाद्य वस्तुओं की तुलना में खास महत्व प्राप्त किया है। पिछले कुछ चुनावों का रुख बदलने में रोजमर्रा के उपयोग की इस छोटी सी सब्जी ने महत्वपूर्ण भमिका निभाई है।

शायद इसलिए कि प्याज उत्तर भारतीय आहार का आवश्यक अंग है।

बलात्कार और बुजुर्ग लोगों की हत्याएं दिल्ली में सबसे अधिक तेजी से बढ़ती रही हैं। नए कानूनों के बावजूद इन पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है इसलिए दिल्ली को बलात्कार और हिंसक अपराधों की राजधानी का दर्जा भी दिया जाने लगा है।

दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्य दिल्ली में इसकी खपत को पूरा नहीं कर पाते। कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र ने प्याज के मामले में दिल्ली के बाजार में वीटों जैसी क्षमता पा ली है । कभी यही स्थिति चीनी की हुआ करती थी। लेकिन कानून व्यवस्था, खासकर छीना झपटी, बलात्कार और बुजुर्ग लोगों की हत्याएं दिल्ली में सबसे अधिक तेजी से बढ़ती रही हैं। नए कानूनों के बावजूद इन पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है इसलिए दिल्ली को बलात्कार और हिंसक अपराधों की राजधानी का दर्जा भी दिया जाने लगा है। मध्यवर्गीय महानगरीय मतदाता इस स्थिति से अधिक परेशान है और अपने चुनाव में इस मुद्दे को महत्व देगा लेकिन आर्थिक रूप से निम्न वर्ग के मतदाता के सरोकार महंगाई के अतिरिक्त रोजगार की घटती संभावनाओं से होते हैं।

दिलचस्प यह है कि इस बार दिल्ली इन और अन्य मुद्दों पर दोतरफा नहीं, तितरफा लड़ाई में जूझनेवाली है। कांग्रेस और भाजपा के अतिरिक्त इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। अन्ना हजारे के आंदोलन से जन्मी इस पार्टी का अभीष्ट साफ है और इसकी चुनाव–शैली भी अलग है। हालांकि पार्टी के दावे बड़े हैं लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इसमें दोनों प्रमुख दलों को नुकसान पहुंचाने की काफी क्षमता है।

सवाल है कि कौन सी पार्टी अधिक क्षतिग्रस्त होगी। इसीलिए कुछ लोगों का अनुमान है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख दलों के बीच कांटे की लड़ाई में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली का युवा वर्ग सार्वदेशिक स्वभाव का है। उसमें प्रादेशिकता या क्षेत्रीयता सबसे कम दिखाई देती है, इसलिए उस पर अखिल भारतीय मुद्दों का असर सबसे अधिक पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चुनावी नतीजों को यह वर्ग महत्वपूर्ण ढंग से प्रभवित करेगा। दिल्ली पर देश के माहौल का असर पड़ेगा और स्थानीय मुद्दे पिछड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में देश में जिस दल के नेतृत्व का प्रभाव दिखाई देगा, वही दिल्ली में मैदान मार ले जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिर तो यही देखना होगा कि युवा मतदाता को राहुल रिझाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी। ❑

गाँधी को भूल गयी सरकार

प्राचीन काल से ही भारत में प्रशासन की धुरी गांव रहे हैं। गांव ही सामाजिक जीवन के केन्द्र बिन्दु और देश की अर्थव्यवस्था की प्रधान इकाई थे। राष्ट्रीय संस्कृति, समृद्धि और प्रशासन का भव्य भवन इन्हीं पर खड़ा था, इनसे सम्बल प्राप्त होता था। दुनिया के किसी भी देश में भारत जितनी धार्मिक और राजनीतिक क्रान्तियां नहीं हुई हैं। फिर भी उसकी ग्राम समितियों के कार्यों पर कोई आंच नहीं आयी। वे पूरे देश में सदैव स्थानीय हित के कार्यों में लगी रही।

■ निरंकार सिंह

महात्मा गांधी ने देश की आजादी के बाद जिस तरह के गांव और गांव पंचायतों की कल्पना की थी उसका निर्माण हम अभी तक नहीं कर सके हैं। उनकी कल्पना थी कि हर गांव पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित करने वाला देष आज महात्मा गांधी की नीतियों और कार्यक्रमों से बहुत दूर जा चुका है।

कांग्रेस की सरकार ने पंचायती राज कानून तो लागू किया किन्तु गांधी जी की कल्पना के अनुसार ग्राम पंचायतों को स्वावलम्बी बनाने की दिषा में कोई काम नहीं किया। उन्होंने ग्राम सभा से लोकसभा तक के लोकतांत्रिक ढांचे की कल्पना की थी और कहा था कि– ''आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। हर एक गांव के लोगों की हुकूमत या पंचायत का राज होगा। उनके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा। अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी ताकि वह अपना कारोबार खुद चला सकें। सच्चे प्रजातंत्र में नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे आदमी को समान अवसर मिलने चाहिए। इसलिए सच्ची लोकषाही केन्द्र में बैठे हुए दस बीस आदमी नहीं चला सकते, वह तो नीचे से हर एक गांवों के लोगों द्वारा चलायी जानी चाहिए।''

गांव और गांव पंचायतों की कल्पना की थी उसका निर्माण हम अभी तक नहीं कर सके हैं। उनकी कल्पना थी कि हर गांव पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित करने वाला देश आज महात्मा गांधी की नीतियों और कार्यक्रमों से बहुत दूर जा चुका है।

इस दृष्टि से बापू ग्राम पंचायतों के विकास के लिये बहुत उत्सुक थे। उन्होंने कई बार यह बात कही थी कि – ''भारत अपने चन्द शहरों में नहीं बल्कि सात लाख गांवों में बसा हुआ है।''

इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन काल से ही भारत में प्रषासन की धुरी गांव रहे हैं। गांव ही सामाजिक जीवन के केन्द्र बिन्दु और देष की अर्थव्यवस्था की प्रधान इकाई थे। राष्ट्रीय संस्कृति, समृद्धि और प्रषासन का भव्य भवन इन्हीं पर खड़ा था, इनसे सम्बल प्राप्त होता था। दुनिया के किसी भी देष में भारत जितनी धार्मिक और राजनीतिक क्रान्तियां नहीं हुई हैं। फिर भी उसकी ग्राम समितियों के कार्यों पर कोई आंच नहीं आयी। वे पूरे देष में सदैव स्थानीय हित के कार्यों

में लगी रही। यहां यूनानी अफगान, मंगोल, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि आकर शासक बने किन्तु गांवों के धार्मिक, व्यापारिक संगठनों का काम यथावत चलता रहा। इस बारे में 1830 में अंग्रेज गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ ने जो ब्यौरा अपने देष को भेजा था उसमें यह लिखा है कि – 'भारत के ग्राम समुदाय एक प्रकार के छोटे–छोटे गणराज्य हैं, जो अपने लिए आवष्यक सभी सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं तथा किसी प्रकार के बाहरी सम्पर्क से मुक्त हैं। लगता है कि इनके अधिकारों और प्रबन्धों पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक के बाद एक राजवंष आता है, क्रांतियों का क्रम चलता रहता है। किन्तु ग्राम समुदाय उसी ढर्रे पर चलता जाता है।

मेरे विचार से ग्राम समुदायों के इस संघ ने जिसमें प्रत्येक (समुदाय) एक छोटे मोटे राज्य के ही रूप में है, अन्य किसी बात की अपेक्षा अनेक क्रान्तियों के बावजूद भारतीय जन समाज को कायम रखने और जनजीवन को विश्रृंखल होने से बचाने में बड़ा भारी काम किया। साथ ही यह जनता को सुखी बनाये रखने और उसे स्वतंत्र स्थिति का उपभोग कराने का बड़ा भारी साधन है। इसलिए मेरी इच्छा है कि गांवों की इस व्यवस्था में कभी उलट फेर न किया जाय। मैं उस प्रवृत्ति की बात सुनकर ही दहल जाता हूँ जो इनकी व्यवस्था भंग करने की सलाह देती है।''

मेटकाफ के इस खौफ के बावजूद ब्रिटिष सरकार स्वतन्त्रता और आत्मनिर्भरता के इन केन्द्रों को विनष्ट करने की निर्धारित नीति पर बराबर चलती रही। भारत का पाला पहली बार ऐसे आक्रामक से पड़ा, जिसने यह काम कर दिखाया, जो बहुत पहले किसी ने नहीं किया था। इन ग्राम–गणतंत्रों को विनष्ट कर ब्रिटिष साम्राज्यषाही ने इस प्राचीन देष को सबसे अधिक क्षति पहुंचायी। यदि 80 प्रतिषत भारतीयों को आश्रय देने वाले हमारे गांवों में पौर प्रषासन का वह पुराना ओज आज भी कायम रहता तो सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय पुनर्निमाण मिनटों की बात थी।

1830 को बीते केवल 173 वर्ष हुए, किन्तु उस गौरवपूर्ण अतीत की धुंधली रेखा भी आज निरक्षर ग्रामीणों ही नहीं, सुषिक्षित नर–नारियों के मानस पटल पर भी नहीं रह गयी है। हमारी अद्‌भुत षिक्षा प्रणाली का यह भी एक कमाल है। कुछ लोगों को बड़ा आष्चर्य होता था कि पौरीकरण (नगरीकरण) के इस युग में भी क्यों गांधीजी का आग्रह बराबर गांवों के लिए रहता है और क्यों वे 'आत्मनिर्भर' स्वषासित ग्राम–गणतंत्रों की वकालत करते नहीं अघाते।

देश की गरीबी तब शुरू हुई जब हमारे शहर विदेशी या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माल के बाजार बन गये और विदेशियों का सस्ता और उपभोग की वस्तुओं को गांवों में भेजकर उनका शोषण करने लगे। अब यह बात भी साबित हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति या देश यदि उत्पादक नहीं, सिर्फ उपभोक्ता है तो उसका पतन निश्चित है। व्यक्ति पहले उत्पादक हो फिर उपभोक्ता हो तभी उसका अस्तित्व बचा रहेगा।

गांधी जी का यह आग्रह इसलिए था कि वे जानते थे कि किसी समय गांवों की क्या हालत थी। वे चाहते थे कि गांवों के सजीव, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधार पर ही उनकी कल्पना का भारतीय लोकतंत्र राज्य कायम हो। दूसरी बात यह है कि गांधी जी प्रत्येक बात पर अहिंसा की दृष्टि से विचार करते थे। उन्होंने यह अनुभव किया था कि जिस राष्ट्रीय निर्माण की मैने कल्पना कर रखी है, उसका आधार गांवों का स्वषासित आत्मनिर्भर सहयोगात्मक, सामुदायिक जीवन बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत करता है।

परन्तु ऐसे प्रयत्न का महत्वपूर्ण परिणाम तो नैतिक है। जब आदमी अपनी ही कुषलता और सतत प्रयत्न से कोई आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान वस्तु बना सकता है, तो उसे स्वाभिमान, आत्मविष्वास, आत्मनिर्भरता, साहस, आषा, स्वतंत्र सूझ–बूझ और शक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद वह अधिक कठिन काम, ऐसा काम जिसमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना पड़े, करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। अगर उसके साथ दूसरे भी ऐसा ही करते हैं तो उन सबमें सामूहिक साहस और सामूहिक आषा का संचार होता है। यह कोरा सिद्धांत नहीं है। क्योंकि गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के किसान गांधी जी के कार्यक्रम की प्रेरणा और पथ–प्रदर्षन से अपने ही सादे औजार से ऐसी चीजें बनाते रहे हैं और साथ–साथ अपने चरित्र और नैतिक बल का निर्माण भी करते रहे हैं। इस दौरान खादी की आष्चर्यजनक प्रगति हुई। अंग्रेजी राज्य के विरूद्ध चलने वाले असहयोग आंदोलन के दिनों वही जिले अत्याचार का अहिंसक मुकाबला करने में सबसे अधिक साहसी, दृढ़ और सफल रहे, जहां हाथ–कताई, हाथ–बुनाई और ग्रामोत्थान के दूसरे काम कुछ वर्षों से चल

रहे थे। हमारे गांव शहरों की सारी जरूरतें पूरी करते थे और उन्हें देते थे। देष की गरीबी तब शुरू हुई जब हमारे शहर विदेषी या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माल के बाजार बन गये और विदेषियों का सस्ता और उपभोग की वस्तुओं को गांवों में भेजकर उनका शोषण करने लगे।

अब यह बात भी साबित हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति या देष यदि उत्पादक नहीं, सिर्फ उपभोक्ता है तो उसका पतन निष्चित है। व्यक्ति पहले उत्पादक हो फिर उपभोक्ता हो तभी उसका अस्तित्व बचा रहेगा।

अर्थव्यवस्था के मौजूदा संकट ने एक बार फिर हमें आर्थिक सुधार की नयी नीतियों की पुनर्विचार का मौका दिया है। अब यह बात साबित हो चुकी है कि किसी भी देष का विकास अन्ततः उसके आन्तरिक संसाधनों और शक्ति पर ही निर्भर करता है। विदेषी पूंजी विदेषी तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता से नई तरह की गुलामी का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए बहुत से लोगों को अब यह महसूस होने लगा है कि गांधी जी के दिखाये रास्ते को छोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती की है। अतः अब तमाम लोग गांधी जी की विचारधारा से मिलता जुलता विचार रखने लगे हैं। जैसे कि कृषि विकास हमारी विकास योजना का मुख्य आधार बनना चाहिए। इसकी बुनियाद पर ही गृह उद्योगों और ग्रामोद्योग की एक रूपरेखा गावों के विकास के लिए बनानी चाहिए। उसमें बिजली, परिवहन और बाजार आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाय। यह बड़े उद्योगों की उपेक्षा का सवाल नहीं है किन्तु अपने देष में जहां पूंजी की बहुत कमी हो और मानव शक्ति बड़े पैमाने पर बेकार पड़ी तथा देष की अधिकांष आबादी गांवों में बसती हो, वहां योजना की बुनियाद बदलनी चाहिए।

विदेशी पूंजी विदेशी तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता से नई तरह की गुलामी का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए बहुत से लोगों को अब यह महसूस होने लगा है कि गांधी जी के दिखाये रास्ते को छोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती की है। अतः अब तमाम लोग गांधी जी की विचारधारा से मिलता जुलता विचार रखने लगे हैं। जैसे कि कृषि विकास हमारी विकास योजना का मुख्य आधार बनना चाहिए। इसकी बुनियाद पर ही गृह उद्योगों और ग्रामोद्योग की एक रूपरेखा गावों के विकास के लिए बनानी चाहिए।

ग्राम पंचायत का इतिहास

प्राचीनकाल में गांवों की व्यवस्था का संचालन समूचे गांव की महासभा (वेदकालिक सभा) करती थी। इस महासभा की बैठक में भाग लेने का अधिकार प्रत्येक गृहपति को था और नगाड़ा बजाकर लोगों को इसकी बैठक के समय आमंत्रित किया जाता था। आगे चलकर जब व्यवस्था अपेक्षाकृत जटिल होती गयी और काम बढ़ता गया तो निर्वाचित ग्राम परिषदों का रूप सामने आया। जिन्हें गुप्त शासनकाल में अथवा उत्तर गुप्त काल में मध्य भारत में महामंडली, बिहार में ग्राम, जनपद, राजपूताना में पंचकुल और तमिलनाडु में आलंगनम् आदि नामों से जाना जाता था। बाद में इसका नाम ग्राम पंचायत हो गया। दक्षिण भारत के बड़े और अपेक्षाकृत अधिक संघटित गांवों की प्रषासन व्यवस्था निर्वाचित उपसमितियों द्वारा संचालित होती थी। आज भी चिंगलपेट जिले में उत्तर पुलुर नाम का एक गांव है, जिसकी प्रषासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। पहले इस गांव का नाम उत्तर मेरूर था।

बुनियादी तालीम

बुनियादी तालीम से विद्यार्थी अपनी षिक्षा, कताई, टोकरी बनाना, बढ़ईगिरी या कुम्हार–काम जैसी किसी हाथ की कारीगरी के जरिये शुरू करता है। इस काम में नापने की जरूरत पैदा होती है, जिससे वह गणित सीखना शुरू करता है। उसका सामान कौन से स्थानों से प्राप्त होता है, उसकी जानकारी प्राप्त करके वह भूगोल सीखता है। किसी वस्तु के आरंभ या मूल की षिक्षा से वह प्रारम्भिक इतिहास सीखता है। उसे सूचनायें पढ़नी पड़ती हैं और काम का लेखा जोखा रखना पड़ता है। इसलिए वह लिखना पढ़ना

बुनियादी तालीम से विद्यार्थी अपनी शिक्षा, कताई, टोकरी बनाना, बढ़ईगिरी या कुम्हार–काम जैसी किसी हाथ की कारीगरी के जरिये शुरू करता है। इस काम में नापने की जरूरत पैदा होती है, जिससे वह गणित सीखना शुरू करता है। उसका सामान कौन से स्थानों से प्राप्त होता है, उसकी जानकारी प्राप्त करके वह भूगोल सीखता है। किसी वस्तु के आरंभ या मूल की शिक्षा से वह प्रारम्भिक इतिहास सीखता है। उसे सूचनायें पढ़नी पड़ती हैं और काम का लेखा जोखा रखना पड़ता है।

सीखता है। जब वह माल खरीदता है या अपना तैयार माल बेंचता है। तब वह अर्थषास्त्र का विषय शुरू कर देता है। ऐसे प्रत्येक विषय की बुनियाद किसी ठोस, दैनिक वास्तविकता और मूल्य पर होती है। सारी षिक्षा का जीवन से सम्बन्ध बंध जाता है। हाथ के काम का गौरव और मूल्य बढ़ता है। षिक्षा के साथ विद्यार्थी का चरित्र गठन भी होता है। वह दूसरों के साथ काम करना सीखता हे। उसमें स्वच्छता, सफाई, व्यवस्थिता, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, आत्मविष्वास, सूझ–बूझ, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता, दूरदृष्टि और कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये सब बातें लड़के लड़की दोनों पर लागू होती हैं। बच्चे घर में काम आने वाला कपड़ा या दूसरी चीजें तैयार करते है। इसलिए माता–पिता उन्हें स्कूल भेज सकते हैं। इस रचनात्मक कार्य के दूसरे अंग विकसित होने पर ग्राम, राज्य और राष्ट्र को एक दूसरे में पिरोकर एक सांमजस्यपूर्ण परस्पर सहायक और परस्पर विष्वास रखने वाला घटक बना देते हैं। ये आम जनता को ऊपर उठाकर उसे आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिज्ञ स्तर पर पहुंचा देते हैं। वे पुराने संघर्ष, विरोध, द्वेष, अहंकार और फूट आदि अन्य सामाजिक बुराईयों को मिटाने में बड़ी मदद करते हैं।

इस तरह बंद हुये गांव के धंधे

केन्द्र एवं राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हमारे गांवों के परम्परागत उन उद्योग–धंधों को नहीं बचा सकी जो कभी उनकी जीविका और अर्थव्यवस्था के आधार थे। शहरों की उपभोक्तावादी ऐसी संस्कृति का प्रचार–प्रसार हुआ जो गांवों के लोगों की बदहाली और बेरोजगारी का कारण बन गया है।

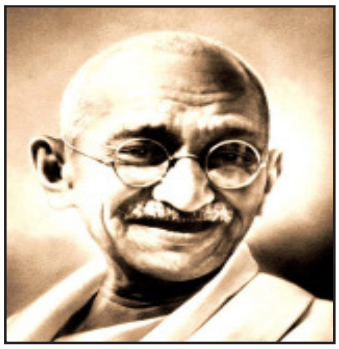

तमाम तरह की मशीनों ने भी गांव वालों को बेरोजगार बनाने का काम किया है। धान की कटाई मड़ाई से लेकर आटा पीसने, धान कूटने और कोल्हू बैल से तेल पेरने का काम भी अब मशीनें कर रही हैं। इस तरह के तमाम कामों में लगे मजदूर किसान अब बेरोजगार हो गये हैं। इससे गांव की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। इस तरह की तमाम उपभोग की वस्तुओं के लिए अब हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर आश्रित हो गये हैं। जिससे देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।

उदाहरण के लिए दातुन के बदले तरह–तरह के दन्त मंजन, पेस्ट, टूथब्रष; गुड़ और राब की जगह मिल की सफेद चीनी; लकड़ी की सुतली या निवाड़ से बनी खाट या पलंग के बदले लोहे के पाइप या छड़ के पलंग; खपरैल की जगह टिन; सन, पटुए, मूंज आदि की रस्सियों की जगह तार और प्लास्टिक की डोरियां; देहाती चटाई के बदले चीनी और जापानी चटाइयां; गांवों में बांस या घास के बने हुये सूप, दौरे–दौरी, पिटारी आदि के स्थान पर टिन या प्लास्टिक के सूप, डब्बे आदि; पेड़ों के पत्तों से बनी पत्तल की जगह प्लास्टिक की पत्तलें, कुम्हार के घड़े, सुराही, कुल्हड़ की जगह प्लास्टिक की गिलासें; थर्मस आदि; देहाती लुहार या कसेरे की बनाई जंजीर, कड़ियों, हत्थे के बदले मषीन से बने तार या पत्तर की वैसी ही कमजोर परन्तु आकर्षक चीजें; देहात के सुनार के बनाये गहनों की जगह शहरों में मषीनों से तैयार हुए गहने; देहाती महिलाओं द्वारा गूंथे पंखे, कढ़े आसन, जाजिम, शाल आदि; रीठा, षिकाकाई इत्यादि प्राकृतिक वस्तुओं के बदले सुगन्धित साबून एवं शैम्पू; नरकट के बदले तरह तरह के बाल एवं जेल पेन और उनके फलस्वरूप देहाती रोषनाई के बदले, रसायनिक रोषनाइयां; देहात के कागज की जगह मषीन के कागज; घरेलू ताजे काढ़े की और अर्को के बदले तैयार दवाइयों की बोतलें आदि; के कारण गांवों की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंची है और तमाम लोग बेकार हो गये हैं।

गांवों में सूत कताई का काम भी लगभग बंद ही हो गया है। जो ग्रामीणों की आमदनी का अच्छा जरिया था। इसके अलावा तमाम तरह की मषीनों ने भी गांव वालों को बेरोजगार बनाने का काम किया है। धान की कटाई मड़ाई से लेकर आटा पीसने, धान कूटने और कोल्हू बैल से तेल पेरने का काम भी अब मषीनें कर रही हैं। इस तरह के तमाम कामों में लगे मजदूर किसान अब बेरोजगार हो गये हैं। इससे गांव की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। इस तरह की तमाम उपभोग की वस्तुओं के लिए अब हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर आश्रित हो गये हैं। जिससे देष को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ❑

अवैध खनन द्वारा नदियों से खिलवाड़

बगैर ज्यादा लागत के ये बहुत मुनाफे वाला सौदा है लेकिन अंधाधुंध और अनियंत्रित बालू उत्खनन से नदी के किनारों का घिसाव होता है जिसका परिणाम जैविवविधता के नुकसान के रूप में सामने आता है। किनारे कटने से वहां पनपने वाली वनस्पतियां नष्ट होती हैं और वहां पलने वाले जीव–जंतुओं का प्राकृतिक आवास समाप्त होता है. . बालू का कोई और सस्ता सुलभ विकल्प न होने का कारण उसका अवैध खनन होता है जिसकी कीमत हमारी नदियां चुकाती हैं। उत्तराखंड हादसा हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जिसने हमें चेताया। पर इस चेतावनी को समझने के लिए हजारों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, सैकड़ों घायल हुए और बेघर भी।

■ मुकुल श्रीवास्तव

रोटी कपड़ा और मकान के संकट से जूझते एक आम भारतीय के लिए पर्यावरण या उससे होने वाला नुकसान अभी भी कोई मुद्दा नहीं है और अवैध बालू खनन भी एक ऐसा ही मामला है जो हमें महज एक कानूनी मसला लगता है। बालू के अवैध खनन के पीछे एक बड़ा कारण इसका भारी होना भी है जिसके कारण बालू को दूर तक ले जाना मुश्किल होता है। इसलिए निर्माण कंपनियां आसपास के इलाकों से बालू निकालने को प्राथमिकता देती हैं। बालू का इस्तेमाल कंक्रीट में मिलाने और ईटें बनाने के लिए किया जाता है।

हालांकि सरकार ने बालू खनन के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की है, पर मांग बहुत ज्यादा है जिससे लाइसेंस व्यवस्था को लगातार अनदेखा कर अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है। बगैर ज्यादा लागत के ये बहुत मुनाफे वाला सौदा है लेकिन अंधाधुंध और अनियंत्रित बालू उत्खनन से नदी के किनारों का घिसाव होता है जिसका परिणाम जैविवविधता के नुकसान के रूप में सामने आता है। किनारे कटने से वहां पनपने वाली वनस्पतियां नष्ट होती हैं और वहां पलने वाले जीव–जंतुओं का प्राकृतिक आवास समाप्त होता है। इसके परिणामस्वरूप नदी के पानी को धारण करने और नदी को दोबारा जल मुहैया कराने वाली व्यवस्था को हानि पहुंचती है। पर अंधाधुंध विकास के चक्कर में इसकी परवाह किसे है क्योंकि विकास का आकलन आर्थिक नजरिए से किया जाता है। यही कसौटी भी है और यही परिणाम भी।

उपभोक्तावाद ने हमें इतना अधीर कर दिया है कि विकास का मापदंड सिर्फ भौतिकवादी चीजें और पैसा ही रह गया है। पक्के निर्माण के बढ़ते चलन और प्रकृति प्रदत्त चीजों पर निर्भरता कम होने का परिणाम है बढ़ता शहरीकरण। आज गांव सिमट रहे हैं और शहर भर रहे हैं। चूंकि गांवों में अभी भी आधारभूत ढांचे का अभाव है इसलिए आर्थिक रूप से थोड़ा–बहुत हर ग्रामीण शहर में बसने के सपने देखता है या शहर की तरह गांव में पक्का घर का निर्माण चाहता है और यह प्रक्रिया आवास निर्माण उद्योग में क्रांति ला रही है और पक्के निर्माण विकसित होने की निशानी माने जा रहे हैं। देश की तरक्की के लिए विकास जरूरी है पर अनियोजित विकास, समस्याएं ही बढ़ाएगा जिसकी कीमत आज नहीं तो कल हम सबको चुकानी ही पड़ेगी।

अब समय आ गया है कि पर्यावरण की दृष्टि के अनुकूल बालू का कोई ऐसा विकल्प ढूंढा जाए जिससे अवैध बालू खनन पर रोक लगे और अवैध बालू जैसे लघु खनिजों से संबंधित कानूनों को और कड़ा किया जाए। हमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों से सबक लेना होगा जिन्होंने समय रहते अपने पर्यावरण संबंधी कानूनों को कड़ा किया और यह भी सुनिश्चित किया कि इन कानूनों का कड़ाई से पालन हो।

सन् 2009 में निर्माण उद्योग ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8.9 प्रतिशत का योगदान दिया, जो 2005 के 7.4 प्रतिशत से ज्यादा है। योजना आयोग के अनुसार अगर देश को लगातार बढ़ते रहना है तो 31 मार्च 2017 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष में अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को जीडीपी का दस प्रतिशत करना होगा, जो पहले पांच साल के आठ प्रतिशत से ऊपर होगा। भारत भले ही गांवों का देश हो, पर आज पूरे देश में शहरीकरण की बयार बह रही है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक कुल 121 करोड़ की आबादी में से 37.71 करोड़ लोग शहरो में रहते हैं।

भविष्य में इस तस्वीर की बहुत तेजी से बदलने की संभावना है।

अनुमान के मुताबिक शहरीकरण की वर्तमान दर 31.1 प्रतिशत है जो 2030 तक चालीस प्रतिशत हो जाएगी। बढ़ता शहरीकरण रीयल एस्टेट और आवास जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ा रहा है। आंकड़े के अनुसार पिछले दस सालों में आवास क्षेत्र में बत्तीस प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है। जैसे–जैसे भारत का शहरीकरण बढ़ता जाएगा, वैसे–वैसे मकानों वाली भूमि का आकार बढ़ता जाएगा। यह 2005 के आठ अरब वर्ग मीटर से बढ़कर 2030 तक 41 अरब वर्ग मीटर तक फैल सकता है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अगले पांच सालों में एक ट्रिलियन डॉलर सार्वजनिक और निजी निवेश की जरूरत होगी। यह निवेश सड़कों, विमानपत्तन और नौकरियों में होगा।

अगर ये अनुमानित निवेश हो जाता है, तो बालू जैसे अवसंरचना में लगने वाले कच्चे माल की मांग तीन गुना तक बढ़ जाएगी और बालू आपूर्तिकर्ताओं पर बेतहाशा दबाव बढ़ेगा और ये दबाव कहीं न कहीं अवैध बालू खनन को बढ़ावा देगा। बात जब निर्माण की होती है तब हम सीमेंट के बारे में सोचते हैं। लेकिन सीमेंट तो मात्र जोड़ने वाला एक पदार्थ है, निर्माण का मुख्य अवयव है बालू और पत्थर या ईट। बालू का कोई और सस्ता सुलभ विकल्प न होने का कारण उसका अवैध खनन होता है जिसकी कीमत हमारी नदियां चुकाती हैं। उत्तराखंड हादसा हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जिसने हमें चेताया। पर इस चेतावनी को समझने के लिए हजारों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, सैकड़ों घायल हुए और बेघर भी।

बालू का अवैध खनन मैदानी क्षेत्रों के पर्यावरण को कितनी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है इसका वास्तविक आकलन होना अभी बाकी है, पर हम जिस तरह अपने पर्यावरण से खेल रहे हैं वह वास्तव में एक खतरनाक खेल है। कानून में बड़े खनिजों जैसे कोयले, हीरे अथवा सोने के विपरीत रेत को 'लघु खनिज' कहा जाता है। कानूनन पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खनन लीज के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति लेना आवश्यक है।

हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अपने दिए एक आदेश में अब पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र में भी खनन

को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या संबंधित राज्य के पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण से अनुमति को अनिवार्य कर दिया है। खान और खिनज (विकास और नियामक) एक्ट 1957 (मई 2012 में संशोधित) के मुताबिक रेत खनन करने वालों को राज्य के प्राधिकारियों से एक लाइसेंस लेना होता है और बालू की मात्रा के मुताबिक शुल्क देना होता है। यह बिक्री दाम का करीब आठ प्रतिशत हो सकता है।

बगैर अनुमति बालू खोदने की सजा दो साल तक की जेल या 25 हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। अवैध रेत खनन को रोकने को लेकर समस्या यह है कि निर्माण में बालू के ज्यादा विकल्प नहीं हैं और जो विकल्प हैं भी वे बालू के मुकाबले महंगे हैं। पर्यावरण जागरूकता के अभाव में और ''जरा–सा बालू निकालने से नदी कौन–सी सूख जाएगी'' वाली मानसिकता नदियों के प्रवाह तंत्र को प्रभावित करके पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है।

अब समय आ गया है कि पर्यावरण की दृष्टि के अनुकूल बालू का कोई ऐसा विकल्प ढूंढा जाए जिससे अवैध बालू खनन पर रोक लगे और अवैध बालू जैसे लघु खनिजों से संबंधित कानूनों को और कड़ा किया जाए। हमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों से सबक लेना होगा जिन्होंने समय रहते अपने पर्यावरण संबंधी कानूनों को कड़ा किया और यह भी सुनिश्चित किया कि इन कानूनों का कड़ाई से पालन हो। ❑

समाचार परिक्रमा

अमरीका में शट डाउन

अपने को सुपर पावर कहलाना वाला देश आज खुद एक बड़े संकट में फंसा पड़ा हुआ है। आज अमरीका के पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है जिसके कारण उसने करीब सात लाख कर्मचारियों को अवैतनिक छुट्टी पर भेज दिया है। विष्व की मजबूत आर्थिक स्थिति वाले सुपर पावर की ऐसी हालात देखकर अनेक देष भी चिंतित है। अमरीका प्रषासन ने शट डाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। शट डाउन के आदेष अमरीकी संसद (सीनेट) द्वारा बजट को मंजूरी नहीं मिलने के बाद दिए गए। इसके साथ ही 7 लाख कर्मचारीं अवैतनिक छुट्टी पर भेज दिए गए। अब उन्हें तब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक यह मुद्दा हल नहीं हो जाता। इसके साथ ही यूएस के राष्ट्रीय पार्क और म्यूजियम बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई कर्मचारी ही नहीं बचा है। साथ ही बुजुर्गों को मिलने वाले चेक देरी से मिलेंगे और वीजा–पासपोर्ट भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। इस दौरान जरूरी विभागों को छोड़कर सभी विभाग के कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया है। अमरीका में क्यों बनी ऐसी स्थिति इसका कारण है 17 सालों में पहली बार आए इस संकट का प्रमुख कारण बजट को वहां की सीनेट से मंजूरी नहीं मिलना है। इसकी वजह सरकार के खर्चों पर संकट पैदा हो गया। बजट को पास कराने के लिए रिपब्लिकन पार्टी और सत्ताधारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी में काफी खींचतान हुई, लेकिन बजट पास नहीं हो पाया जिसकी वजह से स्थिति पैदा हुई। अमरिकी इतिहास पिछले 50 सालों में चार बार शट डाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जोकि समय रहते सुधार ली गई और अमरीका दिवालिया होने से बच गया। ये स्थितियां क्रमषः 1971, 1974, 1990 और 1995 में उत्पन्न हुई थी। ❑

अमरीका संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरा

अमेरिका में मौजूदा ऋण संकट को अति नाजुक करार देते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अमेरिका को चेताया है कि आसन्न ऋण संकट न केवल उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था, बल्कि संपूर्ण वैष्विक अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल सकता है। आईएमएफ के प्रबंध निदेषक क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा, बजट व ऋण सीमा को लेकर जारी राजनीतिक अनिष्चितता से कोई फायदा नहीं। सरकारी कामकाज ठप्प होना काफी खराब है, लेकिन ऋण सीमा नहीं बढ़ाया जाना और भी खराब होगा। इससे न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो सकता है, बल्कि संपूर्ण वैष्विक अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इसलिए यह बहुत नाजुक घड़ी है जिसे जितनी जल्द हो सके, हल किया जाना चाहिए।

अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने कहा है कि भारत और ब्राजील जैसे उभरते देषों के सामने मौजूदा आर्थिक कठिनाइयों से सहज तरीके से उबरना सबसे बड़ी चुनौती है। आईएमएफ का सुझाव है कि इन देषों की विनिमय दर गिर रही है तो उसे गिरने दिया जाए पर इनकी दीर्घकालीन वृद्धि के रास्ते में पड़ी अड़चनों को दूर किया जाए। अब कुछ देषों को दीर्घकालिक वृद्धि के रास्ते आ रही बाधाओं को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने भारत व ब्राजील जैसे देषों में ढांचागत निवेष में तेजी लाने, वित्तीय बाजारों को और व्यापक बनाने तथा और व्यापार व्यवस्था उदार बनाने की आवष्यकता पर जोर दिया। ❑

महंगाई से जेब हुई खाली तो कैसे मनेगी दिवाली

आज देश में बढ़ती महंगाई के कारण मध्यम वर्ग और कम आय वर्ग वाले परिवारों का जीना दूभर हो गया है। जैसे–जैसे दिवाली पास आ रही है तो मध्यम वर्ग और कम आय वर्ग के लोगों ने त्यौहारों के खर्च में 40 प्रतिशत की कटौती करने पर मजबूर हो गए हैं। इसका कारण है बढ़ती महंगाई, रोजगार के घटते अवसर और आय में कमी।

यह जानकारी उद्योग मंडल एसोचौम के एक अध्ययन के निष्कर्ष में सामने आया है। से निकला है। अध्ययन में शामिल मध्यम और कम आय वाले परिवारों में से 72 प्रतिषत का कहना है कि वह दिवाली पर खर्च किए जाने वाले बजट को 40 प्रतिषत तक कम करने पर मजबूर होंगे। सर्वेक्षण के मुताबिक इन वर्ग के लोगों ने कहा कि वह अपनी मासिक आय का औसतन करीब 25 प्रतिषत ही दिवाली पर खर्च करेंगे।

एसोचौम महासचिव का कहना है कि चाहे रुपए में गिरावट हो या खाद्य महंगाई की दर दुगनी हो जाए अमीरों की दिवाली पर किसी प्रकार का असर पड़ने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। जिन 72 प्रतिषत ने दीपावली के बजट में कटौती की बात कही, उनमें से 57 प्रतिषत का कहना था कि वह सेल अथवा छूट के दौरान ही खरीदारी करेंगे। पिछले कुछ माह में सब्जियों और बेकरी उत्पादों ने घरेलू खर्च के बजट को खासा बढ़ाया है। लोगों का कहना है कि जब उनकी कमाई पर असर पड़ा और खर्च बढ़ता जा रहा है तो यह त्योहारों पर व्यय की जाने वाली राषि पर तो असर पड़ना लाजिमी है। ❑

संकट से जल्द उबरेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

देश के प्रसिद्ध उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेष अंबानी ने देष की अर्थव्यवस्था के जल्द ही पटरी पर लौटने का भरोसा जताया है और उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में तमाम आषंकाओं को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखने की जरूरत है। अंबानी ने यहां बात मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा, भारत को अर्थव्यवस्था के उतार–चढ़ाव से आगे देखना चाहिए। उन्हें भरोसा है कि तमाम नकारात्मकता के बावजूद भारत एक महाषक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। मेरा मानना है कि बाधाओं पर ध्यान रखकर आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। इसके बजाय बाधाओं को दूर करने के लिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। ❑

गोल्ड लोन के नियम अब और कड़े

मुसीबत में फंसने पर जो लोग सोने को गिरवी रखकर ऋण लेते थे अब रिजर्व बैंक ने ऋण के नियम काफी सख्त कर दिए हैं। अब गिरवी रखे जाने वाले स्वर्ण आभूषण का मूल्यांकन 22 कैरेट के सोने की पिछले 30 दिन की औसत कीमत के अनुसार किया जाएगा। साथ ही यह कीमत बांबे सराफा संघ (बीबीए) की कीमतों पर आधारित होगी। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा, मूल्यांकन के मानकीकरण और गिरवी रखे जाने वाले स्वर्ण आभूषण का मूल्यांकन बांबे बुलियन एसोसिएषन द्वारा किया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को ऋण के लिए स्वर्ण आभूषण गिरवी रखते समय अपने लेटर हेड पर ग्राहक को सोने की शुद्धता और वजन का प्रमाण पत्र देना होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यदि सोने की शुद्धता 22 कैरेट नहीं है तो एनबीएफसी को 22 कैरेट में तब्दील करना होगा और गिरवी रखे जाने वाले जेवरात का सही वजन बताना होगा। दूसरे शब्दों में कम शुद्ध सोने वाले जेवरात का आकलन उसी अनुपात में होना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि ग्राहक को सोने के जेवरात के मूल्य के 60 प्रतिषत के बराबर ऋण दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने यह व्यवस्था भी दी है कि 20 ग्राम से ज्यादा का सोना गिरवी रखने वाले ग्राहकों को उस सोने पर खुद का मालिकाना हक साबित करना होगा और इसके लिए के दस्तावेजी सबूत पेष करने होंगे। ❑

देश की आर्थिक वृद्धि दर घटी

फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 4.8 फीसद कर दिया है। फिच के अनुसार कमजोर मांग से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर प्रभावित होगी। फिच द्वारा जारी ''वैष्विक आर्थिक परिदृष्य'' रिपोर्ट में कहा गया है कि मई के बाद से घरेलू मुद्रा में 20 फीसद की गिरावट से अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार की संभावनाएं और कम हुई हैं। इससे पहले फिच ने जून में 2013–14 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.7 फीसद रहने का अनुमान लगाया था। देष की वृद्धि दर के अनुमान में ऐसे समय में कमी की गई है जब उसके समक्ष धीमी वृद्धि दर, विनिमय दर तथा चालू खाते के घाटे की चिंता है। ❑

अमरीका के धनकुबेरों में तीन भारतीय शामिल

भारतीय प्रतिभा किसी से छिपी नहीं है हाल ही में अमरीकी धनकुबेरों में अब तीन भारतीयों का नाम भी शामिल हो गया है। 400 धनकुबेरों के सूची में तीन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक भरत देसाई, रोमेष टी. वाधवानी और विनोद खोसला शामिल है। माइक्रोसाफ्ट के बिल गेट्स फोर्ब्स की अमीरों की सूची में स्थान पाने में सफल रहे हैं। बिल गेट्स की कुल संपत्ति 72 अरब डालर आंकी गई है। अमेरिकी भारतीय धनकुबेरों में फ्लोरिडा में आउटसोर्स कारोबार करने वाले भरत देसाई और उनका परिवार शामिल है। इन्हें सूची में 252 वां स्थान मिला है और इनकी शुद्ध परिसंपत्ति 2.2 अरब डालर आंकी गई है। इसके अलावा अन्य अमेरिकी भारतीयों में कैलिफोर्निया के साफ्टवेयर निर्माता रोमेष टी. वाधवानी तथा विनोद खोसला शामिल हैं। वाधवानी 2.1 अरब डालर की संपत्ति के मालिक हैं तो खोसला डेढ़ अरब डालर संपत्ति है।❑

मोदी की रैली ने सभी दलों की नींद उड़ाई

नरेन्द्र मोदी की भाजपा के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के बाद उनकी देषव्यापी रैलियों से कांग्रेस के साथ ही क्षेत्रीय दलों की भी नींद उड़ी हुई है। मोदी की रैलियों में उमड़ रहे जनसैलाब और युवाओं में बढ़ रहे उनके प्रति क्रेज से क्षेत्रीय दलों के समीकरण अब गड़बड़ाने शुरू हो गए हैं। मोदी जिस तरह से विकास, रोजगार का नारा और देशभक्ति की भावना लेकर चल रहे हैं उससे क्षेत्रीय दलों में खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेष और बिहार में सपा, बसपा, जदयू, राजद और लोजपा जैसे दलों में हड़कम्प मचा हुआ है। यही हाल कांग्रेस का भी है।❑

देश में 4.7 प्रतिशत है बेरोजगारी का अनुमान

घटते रोजगार से एक तरफ देश के प्रत्येक गांव और शहरों में बेरोजगारी बढ़ रही है वही दूसरी ओर हाल ही में जारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम कार्यालय द्वारा जारी वार्षिक रोजगार एवं बेरोजगार सर्वेक्षण 2012–13 के मुताबिक, देष में सबसे अधिक बेरोजगार लोग सिक्किम में हैं साथ ही देष की बेरोजगारी दर 4.7 प्रतिषत होने का अनुमान है। जिसमें सबसे अधिक बेरोजगारी की दर सिक्किम में पाई गई, जबकि छत्तीसगढ़ में यह सबसे कम रही। सर्वेक्षण में बताया गया है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में प्रति 1,000 व्यक्ति बेरोजगारी दर सबसे अधिक (136) सिक्किम में रही, जबकि अरुणाचल प्रदेष में यह 130, त्रिपुरा में 126, गोवा में 107 और केरल में 104 रही। दूसरी ओर उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी की दर जम्मू–कष्मीर में दर्ज की गई जो 88 रही। वहीं हिमाचल प्रदेष में यह 63, दिल्ली में 57, चंडीगढ़ में 56 और पंजाब व हरियाणा में यह 48–48 रही। सिंह ने बताया कि देष में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल रहा जहां प्रति 1000 लोगों में यह 14 रही, जबकि कर्नाटक में 20, मध्य प्रदेष में 22, आंध्र प्रदेष में 25 और गुजरात में 27 रही। ❑

अगस्त में रही रुपए में सबसे बड़ी गिरावट

वर्ल्ड फेडेरषन आफ एक्सचेंजेज (डब्ल्यूएफई) द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार एषिया, अमेरिकी क्षेत्र, अफ्रीका, यूरोप तथा पष्चिम एषिया के देषों की मुद्राओं की तुलना में अगस्त माह में डालर के मुकाबले रुपए का प्रदर्षन सबसे कमजोर रहा। अर्थव्यवस्था में सुस्ती तथा निवेषकों के भरोसे में गिरावट से अगस्त में रुपया 8.7 प्रतिषत कमजोर हुआ। अगस्त में रुपया गिरकर 66.07 प्रति डालर तक नीचे आ गया। जुलाई में यह 60.80 प्रति डालर पर था। इस तरह अगस्त में रुपया 8.7 प्रतिषत गिरा। हालांकि, चालू माह में इसमें कुछ सुधार देखने को मिला है। डेलायट हास्किंस एंड सेल्स के भागीदार अतुल धवन ने कहा, वैष्विक निवेष कोष प्रवाह में बदलाव के अलावा भारतीय मुद्रा में गिरावट की प्रमुख वजह ऊंचा चालू खाते का घाटा तथा कर अनिष्चितता के बीच निवेषकों के भरोसे का डगमगाना है। ❑

भारत में पूंजी के बाह्य प्रवाह का खतरा

हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आगाह किया है कि पूंजी के बाह्य प्रवाह के मामले में भारत अति संवेदनषील देषों में शामिल है। मूडीज का कहना है कि भारत काफी हद तक बाहरी वित्तपोषण पर निर्भर करता है। मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट ''अमेरिका के कड़े मौद्रिक रख से एषियाई बाजार कैसे प्रभावित होंगे'' में कहा गया है कि विदेषी वित्तपोषण पर निर्भरता की वजह से भारत व इंडोनेषिया पूंजी के बाह्य प्रवाह मामले में सबसे ज्यादा संवेदनषील देषों में आते हैं। मूडीज के अनुसार अमेरिका में प्रोत्साहन कार्यक्रम में बदलाव होने से ऐसी आषंका है कि देष से पूंजी बाहर निकलने लगेगी और इसका असर रुपए पर पड़ेगा और यह डालर के मुकाबले गिरेगी। शेयरों में भी गिरावट आएगी। इससे पहले 28 अगस्त को डालर के मुकाबले रुपए 68.86 रुपए प्रति डालर तक गिर गया था और फिलहाल यह 62.83 रुपए के आसपास है।❑

कलानिधि मारन सबसे ज्यादा वेतन लेते है

एक ओर देश में बढ़ती महंगाई और घटते रोजगार से लोगों ने अपने खर्च में कटौती करना शुरू कर दिया है वही दूसरी ओर भारत में सूचीबद्ध कंपनियों में सन टीवी प्रवर्तक कलानिधि मारन तथा उनकी पत्नी कावेरी बीते वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा वेतन पैकेज पाने वालों की सूची में है। इन दोनों में प्रत्येक का सालाना वेतन पैकेज 56.25 करोड़ रुपए रहा। इस सूची में इन दोनों ने जिंदल स्टील के नवीन जिंदल को पीछे छोड़ दिया है।

हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती का असर तीनों कार्यकारियों के वेतन पैकेज पर दिखा। तीनों ने ही इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कम पैकेज लिया। आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को उनकी पांच सूचीबद्ध कंपनियों ने 49.62 करोड़ रुपए का वेतन पैकेज दिया और वह सूची में पांचवें स्थान पर रहे।

हीरो मोटो कार्प की पिता–पुत्र की तिकड़ी में बृजमोहन लाल मुंजाल को 32.72 करोड़ रुपए, जबकि पवन मुंजाल को 32.80 करोड़ रुपए और सुनीलकांत मुंजाल को 31.51 करोड़ रुपए का वेतन पैकेज मिला। बीते वित्त वर्ष में सबसे अधिक वेतन पैकेज पाने वाले 10 शीर्ष कार्यकारियों का पैकेज मात्र 4 प्रतिषत अर्थात् 15 करोड़ रुपए बढ़ा और यह 402 करोड़ रुपए तक रहा। ❑

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) की ओर से विदेशी बाजार में रुपए में अंकित एक अरब डॉलर बॉन्ड जारी किया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इससे घरेलू कंपनियों और देश में नौकरियां बढ़ेगी। देखा जाए तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ❑

देश में तेजी से घट रहा भू-जल स्तर

आज देष में भू–जल स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है। अगर यही हाल रहा तो 2025 तक लोग बूंद–बूंद पानी को तरसेंगे। भूजल के गिरते स्तर के प्रमुख कारण है बढ़ते उद्योग–धंधों, बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती आबादी बढ़ती कृषि और घरेलू क्षेत्र में भू–जल का दोहन काफी हो रहा है। सरकार ने प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में तेजी से हो रही कमी को देखते हुए 2013 को जल संरक्षण वर्ष घोषित किया है लेकिन इसमें कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। हाल ही में जारी जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित स्थायी उपसमिति की रिपोर्ट ने स्थिति को भयावह बताया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक देष में 1,093 बिलियम क्वीबिक मीटर (बीसीएम) और सन् 2050 तक 1,447 बीसीएम पानी की जरूरत होगी। इस जरूरत को पूरा करने में करने में भू–जल की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस समय देष में 432 बीसीएम भू–जल है और यह लगातार घट रहा है। दिल्ली में आज करीब 40 प्रतिशत भूजल का दोहन होता है उसके मुकाबले उसका संरक्षण या भंडारण नहीं हो रहा। जबकि यहां पर मात्र 0.29 बीसीमए भूजल है। उत्तर प्रदेष में 68.57 बीसीएम भूजल है। पिछले कुछ वर्षो प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऐसे उद्योग–धंधे लगाए गए, जिनमें भूजल का अनाप–षनाप दोहन हो रहा है मगर उसके भंडारण के विकल्पों पर ध्यान नहीं दिया गया। बिहार में भूजल 26.21 बीसीएम और उत्तराखंड में 0.27 बीसीएम है, यहां पर भूजल का बहुत कम दोहन हो रहा है क्योंकि सतह जल काफी है। लगभग सभी जिलों में भू–जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। अगर भविष्य में जल संरक्षण या भंडारण व्यवस्था नहीं की गई तो 2025 तक लोग बूंद–बूंद पानी को तरसेंगे। ❑

2050 में जनसंख्या में नम्बर वन होगा भारत

फ्रांस में हुए एक अध्ययन के अनुसार इस सदी के मध्य तक भारत पड़ोसी राष्ट्र चीन को पछाड़ कर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देष बन जाएगा। इस नए अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2050 तक दुनिया की जनसंख्या 9.7 अरब पहुंचने की संभावना है। फ्रेंच इंस्टीट्यूट आईएनईडी की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक भारत 1.6 अरब जनसंख्या के साथ विष्व में जनसंख्या के लिहाज से पहले स्थान पर पहुंच जाएगा वही चीन 1.3 अरब जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर खिसक जाएगा। दुनिया की र्वतमान जनसंख्या 7.1 अरब बढ़कर वर्ष 2050 तक 9.7 अरब तक पहुंच जाएगी। फ्रेंच इंस्टीट्यूड के वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता गिल्लस पिसन ने रिपोर्ट में कहा है, पिछले दो सौ वर्षो में दुनिया की जनसंख्या में सात गुना वृद्धि हुई है और 21वीं सदी के अंत तक इसके 10 या 11 अरब पहुंचने की संभावना है।❑

आधार कार्ड के बिना भी मिलेगा सरकारी लाभ : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि आधारकार्ड को अनिवार्य नहीं किया जाए। कोई भी अथारिटी या सरकारी फायदे के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य न करे। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए केन्द्र और राज्य सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं कर सकती। अगर आधार कार्ड न होने की वजह से किसी को सरकारी लाभ से वंचित किया जा रहा है तो वह अदालत की शरण ले सकता है। ❑

सेवा क्षेत्र में गिरावट

एचएसबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ऊंची बयाज दरें और वृहत आर्थिक अनिश्चितता की वजह से देश की आर्थिक मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज देश की जीडीपी में 50 फीसदी से अधिक योगदान रखने वाले सेवा क्षेत्र में सितंबर माह में घटकर चार साल के निचले स्तर पर आ गई है। इससे रोजगार के अवसरों में कमी आने की आशंका काफी बढ़ गई है। सेवा क्षेत्र का उत्पादन सूचकांक सितम्बर में घटकर 44.6 पर आ गया जो अगस्त में 47.6 पर था। रिपोर्ट के अनुसार कम मांग और मुश्किल आर्थिक हालात के बीच नए आर्डर घटने के कारण यह संकुचन हो रहा है। सेवा क्षेत्र के दायरे में बैंक, बीमा, सूचना प्रौद्योगिक (आईटी), होटल एवं पर्यटन, रेलवे, विमान और शिक्षा आदि शामिल है।

देश में औद्योगिक वृद्धि में उतार–चढ़ाव जारी है। ऐसे में जीडीपी में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले क्षेत्र में गिरावट से आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ❑

परिधान निर्यात का हब बनेगा भारत

परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद के अध्यक्ष ए. शक्तिबेल ने कहा है कि अगले पांच साल में परिधान और चुने हुए कपड़ों का सबसे बड़ा केन्द्र भारत बन सकता है।

उन्होंने कहा चीन आज इंजीनियरिंग व सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान दे रहा है और जबकि वे बांग्लादेश को नियमों का पालन नहीं करने वाला देश मानते है, इसलिए पारंपरिक और गैर–पारंपरिक दोनों बाजारों की वैश्विक कंपनियां आउटसोर्सिंग के लिए भारत की ओर देख रही है। ❑

गांव फिर से अर्थव्यवस्था के लिए सहारा

उद्योग मंडल एसोचैम की एक सर्वेक्षण में यह आकलन लगाया गया है कि वैश्वीकरण के इस दौर में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बावजूद गांवों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। आज गांव फिर से अर्थव्यवस्था के लिए सहारा बनने को तैयार है। गांवों की शक्ति में इस बार अच्छे मानसून ने भी काफी साथ दिया है। अच्छे मानसून के चलते खेती–बाड़ी में आर्थिक वृद्धि दर 5.8 फीसदी रहने का अनुमान है।

सर्वेक्षण में कहा गया है देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा भले ही बीते कुछ साल से घटकर 14 प्रतिशत से नीचे चला गया, लेकिन इस क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र पर बहुस्तरीय असर डालेगा। ❑

स्वदेश धन भेजने में चीन से आगे हैं भारतीय

विश्व बैंक के मुताबिक वर्ष 2012 के लिए विदेशों में कार्यरत लोगों से धन प्राप्ति के मामले में भारत के बाद चीन के लोगों ने 60 अरब डॉलर स्वदेश भेजे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के बीच विदेश में रहने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर रहे है। जानकारों का मानना है कि इससे देश की मुद्रा में गिरावट को रोकने में भी मदद मिलती है। ❑

जापानी बुखार का देसी टीका

जापानी बुखार से निपटने के लिए देसी टीका तैयार कर लिया है। पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने इस टीके का निर्माण किया है। तकनीक के वितरण की जिम्मेदारी भारत बायोटेक को दी गई है। ❑

विकासशील देशों पर कृषि बाजार खोलने का दबाव

कृषि उत्पादों के लिए विकासशील देशों का बाजार खोलने की विकसित देशों की मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है। दोहा वार्ता की टूटी कड़ी को जोड़ने के लिए इंडोनेशिया के बाली में होने जा रही विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले विकसित देशों ने इस मुद्दे पर सहमति बनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया है। विकसित देश दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर बाजार को खोलने की मांग कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के नए महानिदेशक रॉबर्टो एजेवेडो ने कहा कि दिसंबर में होने वाली बाली बैठक से पहले इस मुद्दे पर सहमति बना ली जानी चाहिए। विकासशील देशों के बाजार में अपने कृषि उत्पादों की पहुंच आसान बनाने की अमेरिका सहित विकसित देशों की जिद के चलते ही दोहा वार्ता का क्रम टूट गया है। भारत और ब्राजील सहित कई विकासशील देश इस वार्ता की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की कोशिश में लगे हैं। सदस्य देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने बहुपक्षीय बातचीत की परंपरा को बनाए रखने की वकालत की। अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत तमाम विकसित देश द्विपक्षीय समझौतों के जरिये व्यापार बाधाएं दूर करने पर जोर दे रहे हैं। भारत का मानना है कि बेहद कम विकसित देशों के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है। ❑

अमेरिका पर डिफॉल्टर होने का खतरा बढ़ा

अमरीका में शटडाउन चलते उस पर डिफाल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। बजट को मंजूरी नहीं मिलने से अमेरिकी शटडाउन जारी है। अब व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर अप्रत्याशित संकट मंडरा रहा है। दूसरी तरफ चीन ने कहा कि अमेरिका इस आर्थिक संकट को जल्द हल करे वरना इसका असर विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। साथ ही चीन ने चेतावनी दी है कि अगर यही हालात रहे तो उसके निवेश पर भी असर पड़ सकता है। चीन ने अमेरिका को आगाह किया है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो वह अमेरिका में निवेश बंद कर देगा। ❑

वालमार्ट और भारती अब खोलेंगे अलग-अलग स्टोर

भारती एंटरप्राइजेज और वालमार्ट स्टोर्स अब भारत में अलग–अलग बहुब्रांड खुदरा कारोबार करेंगे। इसके साथ ही उनकी छह साल पुरानी संयुक्त कारोबार दोस्ती टूट गई। दोनों कंपनियों ने घोषणा की है कि अब वे भारत में स्वतंत्र रूप से अलग कारोबारी ढांचे का स्वामित्व करने की सहमति बनी है और वे खुदरा कारोबार में अपने फ्रैंचाइजी समझौते को खत्म कर रही हैं। वही भारती एंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन व प्रबंध निदेशक राजन भारती मित्तल ने कहा कि भारती एक विश्वस्तरीय खुदरा उद्यम बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है और वह सभी प्रारूपों में भारती रिटेल में निवेश करना जारी रखेगी। वालमार्ट एशिया के अध्यक्ष व सीईओ स्काट प्राइस ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए स्वतंत्र रूप से परिचालन करने के हमारे निर्णय से दोनों पक्षों को लाभ होगा। ❑

चीन की चिंता - हमारी उम्मीद

चीन की विकास दर तो गिरी ही है, उसकी आबादी में युवाओं की संख्या भी तेजी से कम होती जा रही है, जबकि बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है. .चीन की इन आर्थिक चिंताओं के बीच भारत की उम्मीदें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चीन की कामकाजी आबादी में गिरावट के परिप्रेक्ष्य में भारत की बढ़ी हुई आबादी मानव संसाधन के लिहाज से वरदान सिद्ध हो सकती है। भारत की आबादी में पचास प्रतिशत से ज्यादा संख्या उन लोगों की है, जिनकी उम्र पच्चीस साल से कम है। यदि हम चाहते हैं कि अपने श्रमबल से आर्थिक व औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखें, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।

■ जयंतीलाल भंडारी

इस समय चीन के आर्थिक परिदृश्य पर दो चिंताएं उभर रही हैं। एक, चीन की विकास दर में गिरावट, और दूसरा, वहां की कामकाजी आबादी घटने से श्रमबल में कमी की प्रवृत्ति। यह कोई छोटी बात नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में दहाई से ऊपर पहुंची हुई चीन की विकास दर में गिरावट आई है और अब यह सालाना सात प्रतिशत पर पहुंच गई है।

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश और विकासशील मुल्कों में सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन अपनी अर्थव्यवस्था के बिगड़ते प्रतिमानों से चिंतित है। चीन की राजकोषीय और बैंकिग स्थिति उसके जी. डी.पी. विकास में आने वाली बड़ी गिरावट का संकेत दे रही है।

अध्ययन बता रहे हैं कि चीन अब उत्पादन में दस डॉलर की बढ़ोतरी के लिए चालीस डॉलर खर्च कर रहा है। चीन में किया गया अत्यधिक निवेश वहां के उद्योग व्यवसाय पर असर डाल रहा है। फिच की रेटिंग के अनुसार, चीन का वर्तमान कर्ज बढ़कर देश की कुल जी.डी. पी. के 200 फीसदी तक जा पहुंचा है।

चीन की दूसरी बड़ी आर्थिक चिंता नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग की ताजा रिपोर्टों में दिखाई दे रही है। यह चिंता 'एक दंपति–एक संतान' नीति के कारण श्रमबल घटने के चौंकाने वाले परिदृश्य के रूप में है। सस्ते श्रमबल के आर्थिक मॉडल पर टिकी चीन की अर्थव्यवस्था में घटते हुए श्रमबल से उत्पादन और विकास दर घटने का सिलसिला शुरू हो गया है।

नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा है कि पिछले वर्ष पहली बार 15 से 59 वर्ष की कार्यशील आबादी में 35 लाख श्रमिकों की कमी आई है। वहां युवा आबादी कम हो रही है, तो बुजुर्गों की बढ़ रही है। अभी चीन की कार्यशील आबादी 94.4 करोड़ है, जो 2020 में घटकर

हमें शैक्षणिक दृष्टि से पीछे रहने वाले युवाओं को रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों से शिक्षित करना होगा। हमें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ढांचागत और भौतिक सुविधाएं विकसित करनी होंगी। चूंकि चीन भारत से औसतन 30 प्रतिशत कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, अतएव चीन से व्यापार में मुकाबला करने के लिए हमें कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने वाले देश के रूप में पहचान बनानी होगी।

92.9 करोड़ रह जाएगी।

अब तक चीन अपनी भारी कामकाजी आबादी के कारण दुनिया का कारखाना बना हुआ है, लेकिन भविष्य में चीन के उद्योगों में श्रमबल की भारी कमी होने से उसकी औद्योगिक स्थिति में चिंताजनक बदलाव आएगा। 1980 में 'एक दंपति–एक संतान' नीति लागू करने से वहां की जन्म दर में जोरदार कमी आने लगी है। अपनी आबादी स्थिर रखने के लिए उसे कम से कम 2.2 की प्रजनन दर की जरूरत है, जबकि अभी यह दर 1.66 है। यह भारत की मौजूदा प्रजनन दर 2.6 फीसदी की तुलना में बहुत कम है।

1990 से चीन के स्कूलों में बच्चों की संख्या में भी लगातार कमी आई है। यद्यपि कुछ शहरों में एक बच्चे वाले परिवारों को एक और बच्चे की अनुमति देने वाले पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, लेकिन आशंका है कि ऐसे कार्यक्रम अधिक सार्थक नहीं होंगे।

वस्तुतः चीन की इन आर्थिक चिंताओं के बीच भारत की उम्मीदें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चीन की कामकाजी आबादी में गिरावट के परिप्रेक्ष्य में भारत की बढ़ी हुई आबादी मानव संसाधन के लिहाज से वरदान सिद्ध हो सकती है। भारत की आबादी में पचास प्रतिशत से ज्यादा संख्या उन लोगों की है, जिनकी उम्र पच्चीस साल से कम है। यदि हम चाहते हैं कि अपने श्रमबल से आर्थिक व औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखें, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। हमें शैक्षणिक संस्थानों में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वाले युवाओं को रोजगार बाजार की नई जरूरतों के मुताबिक सुसज्जित करना होगा।

हमें शैक्षणिक दृष्टि से पीछे रहने वाले युवाओं को रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों से शिक्षित करना होगा। हमें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ढांचागत और भौतिक सुविधाएं विकसित करनी होंगी।

हमें इन सभी बुनियादी कमजोरियों को दूर करना होगा। चीन के बदलते हुए श्रमबल परिदृश्य के मद्देनजर नई पीढ़ी को जरूरतों के मुताबिक तैयार करने के लिए सरकार द्वारा ऐसा नया रोडमैप बनाया जाना चाहिए, जिससे भारत दुनिया की नई आर्थिक शक्ति के तौर पर सामने आए।

चूंकि चीन भारत से औसतन 30 प्रतिशत कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, अतएव चीन से व्यापार में मुकाबला करने के लिए हमें कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने वाले देश के रूप में पहचान बनानी होगी। चीन की तरह भारत को भी गुड गवर्नेंस की स्थिति बनानी होगी। प्रतिस्पर्धा में सतत सुधार तथा वित्तीय मानदंडों के प्रति जवाबदेही पर ध्यान दिया जाना समीचीन होगा।

उल्लेखनीय है कि भारत के पास कुशल पेशेवरों की फौज है। आईटी, सॉफ्टवेयर, बीपीओ, फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल्स एवं धातु क्षेत्र में दुनिया की जानी–मानी कंपनियां हैं, आर्थिक व वित्तीय क्षेत्र की शानदार संस्थाएं हैं। दवा निर्माण, रसायन निर्माण और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भारत के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन आर्थिक सुधार, बुनियादी ढांचा, आंतरिक व्यापार, शिक्षित–प्रशिक्षित श्रम शक्ति, वैज्ञानिक अनुसंधान, जवाबदेह प्रशासन, भ्रष्टाचार कम करने के प्रयास आदि की कसौटी पर चीन की तुलना में हम बहुत पीछे हैं।

चीन में 1980 से आर्थिक सुधार तेज गति से आगे बढ़े हैं, जबकि भारत में आर्थिक सुधार 1991 से धीमी गति से शुरू हुए। चीन में आर्थिक सुधारों के तहत अर्थव्यवस्था को देसी–विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा खुला बनाया गया, कृषि और सिंचाई क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया गया, प्रतिस्पर्धा में सतत सुधार पर ध्यान दिया गया, वित्तीय मानदंडों के प्रति जवाबदेही बरती गई और आधारभूत ढांचे के तहत सड़कों, पुलों, फ्लाइओवर, हवाई अड्डों आदि का जाल बिछाया गया।

हमें इन सभी बुनियादी कमजोरियों को दूर करना होगा। चीन के बदलते हुए श्रमबल परिदृश्य के मद्देनजर नई पीढ़ी को जरूरतों के मुताबिक तैयार करने के लिए सरकार द्वारा ऐसा नया रोडमैप बनाया जाना चाहिए, जिससे भारत दुनिया की नई आर्थिक शक्ति के तौर पर सामने आए। ❑

हमारा उद्देश्य है इस राष्ट्र का निर्माण करना, इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना। जब हम कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो राष्ट्रवाद की कसौटी में राष्ट्र के उत्कर्ष की हमारी दृष्टि देश का सबसे छोटा आदमी जो सबसे गरीब, गया-बीता है, उसके उत्कर्ष को हम राष्ट्र का उत्कर्ष मानते हैं। राष्ट्र के उत्कर्ष की यही कसौटी है।

– दत्तोपंत ठेंगड़ी

घोटालेबाजी की ये भी कोई सजा है?

असली सजा तो तब मिलेगी, जब उनकी सारी चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली जाए। उनकी पत्नियों, संतानों और निकट रिश्तेदारों (यदि वे भी उलझे हों तो) की भी संपत्ति की जांच हो और जब्ती हो। जब कानून इतना सख्त होगा, तब भ्रष्टाचार की सोचते ही नेताजी का दिमाग कुंद पड़ जाएगा। नौकरशाह खुद तो भ्रष्टाचार करने से डरेंगे ही, वे भ्रष्टाचारी मंत्री की हां में हां भी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उन्हें भी फंसने का डर रहेगा।

■ **डॉ. वेदप्रताप वैदिक**

चारा घोटाले में दोषी पाए गए नेताओं, नौकरशाहों और ठेकेदारों को मिलने वाली सजा काफी नहीं है। उन्हें अधिक से अधिक सात साल की सजा मिलेगी और जो सांसद और विधायक हैं, उनकी सदस्यता छिनेगी। इस सजा से धांधलेबाज लोगों के दिल में थोड़ा डर तो जरूर पैदा होगा। वे सोचेंगे कि यदि लालू और जगन्नाथ मिश्र जैसे तेज–तर्रार और दबंग नेता भी अंदर किए जा सकते हैं तो अब किसी भी नेता की खैर नहीं है। नौकरशाहों और जजों को फुसलाने की क्या कम कोशिशें हुई होंगी? कुछ के तो प्रमाण भी उपलब्ध हैं।

फिर भी ये लोग शिकंजे में फंस ही गए। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि नेता, नौकरशाह और ठेकेदारों के दिल में कोई दहशत सचमुच पैदा होगी? मुझे लगता है कि बिल्कुल पैदा नहीं होगी, क्योंकि पाँच साल की सजा भी कोई सजा है? 950 करोड़ का घोटाला याने सब घोटालेबाजों ने अपने और अपने परिवार का 100–100 साल का इंतजाम कर लिया है। इतना बड़ा हाथ मारने पर सिर्फ सात साल की सजा? यह तो कुछ नहीं है। जरा सोचिए, 15–20 साल पहले 950 करोड़ रु. की कीमत क्या होगी? और फिर यह तो सिर्फ वह राशि है, जो पकड़ी गई है और सिर्फ एक मामले में पकड़ी गई है। जो पता ही नहीं चली है, वह राशि कितनी होगी?

और जो एक घोटाला कर सकता है, वह हर मामले में घोटाले को तत्पर रहता है। इसीलिए इन घोटालेबाजों की सजा कम से कम आजन्म कारावास होनी चाहिए। इन घोटालाबाजों ने बिहार की अत्यंत गरीब जनता की जेब काटी है, उसका खून चूसा है, उसकी पीठ में छुरा भोंका है। इन 'भद्र लोगों' को इतनी कठोर सजा इसलिए भी मिलनी चाहिए कि ये लोग साधारण अपराधी नहीं हैं। ये भेड़ के वेश में भेड़िए हैं।

आप क्या सोचते हैं कि नेता, नौकरशाह और ठेकेदारों के दिल में कोई दहशत सचमुच पैदा होगी? मुझे लगता है कि बिल्कुल पैदा नहीं होगी, क्योंकि पाँच साल की सजा भी कोई सजा है? 950 करोड़ का घोटाला याने सब घोटालेबाजों ने अपने और अपने परिवार का 100–100 साल का इंतजाम कर लिया है। इतना बड़ा हाथ मारने पर सिर्फ सात साल की सजा? यह तो कुछ नहीं है। जरा सोचिए, 15–20 साल पहले 950 करोड़ रु. की कीमत क्या होगी?

भ्रष्टाचारियों को सिर्फ जेल में रखना काफी नहीं है। उनको असली सजा तो तब मिलेगी, जब उनकी सारी चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली जाए। उनकी पत्नियों, संतानों और निकट रिश्तेदारों (यदि वे भी उलझे हों तो) की भी संपत्ति की जांच हो और जब्ती हो। जब कानून इतना सख्त होगा, तब भ्रष्टाचार की सोचते ही नेताजी का दिमाग कुंद पड़ जाएगा। नौकरशाह खुद तो भ्रष्टाचार करने से डरेंगे ही, वे भ्रष्टाचारी मंत्री की हां में हां भी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उन्हें भी फंसने का डर रहेगा। भ्रष्टाचार से लूटे गए पैसे पर जो–जो लोग मजे करते हैं, उन सबको भी सात–आठ साल की सजा होनी चाहिए। धांधलेबाज की पत्नियों, बच्चों और उन सभी सगे संबंधियों और सहकर्मियों को जेल भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे का उपभोग किया है।

कानून में यह संशोधन कर दिया जाए तो भ्रष्टाचारी नेताओं को उनके घर के लोग ही भ्रष्टाचार करने से रोकेंगे। भ्रष्टाचार के मामलों के निपटारे में 15–20 साल लगना अपने आप में भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारें जिम्मेदार हैं। नया कानून बनना चाहिए कि अधिक से अधिक एक साल में मामला निपटे। चारा घोटाले के इस फैसले से उस काले कानून के खात्मे को बल मिलेगा, जिसका समर्थन सभी दलों के 'मौसेरे भाइयों' ने किया था और जिसे अध्यादेश बनाकर सरकार राष्ट्र पर थोपना चाहती थी। ❑

परमाणु दायित्व कानून से खिलवाड़

अमेरिका से परमाणु करार के दौरान संप्रग सरकार ने दावा किया था कि इस समझौते से भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन सच्चाई है कि पांच साल बाद भी भारत के कई परमाणु रिएक्टर आवश्यक ऊर्जा तथा नवीन टेक्नोलॉजी की अनुपलब्धता के चलते बंद पड़े हैं। अब जब सरकार के कार्यकाल के गिने–चुने दिन रह गए हैं, ऐसे में परमाणु करार पर उसकी हड़बड़ी कई तरह का सवाल खड़ा करती है। समझ से परे है कि वे कौन से कारण हैं, जिसकी वजह से वह अमेरिका के आगे बिछी जा रही है।

■ अरविन्द जयतिलक

केंद्र की संप्रग सरकार देश की सुरक्षा के साथ किस तरह खिलवाड़ करती है, परमाणु दायित्व कानून पर उसके लचर रुख से स्पष्ट हो जाता है। अगर यह सच है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अमेरिकी दौरे में अमेरिका के साथ परमाणु करार तय भारतीय कानून के अनुरूप नहीं होगा तो यह देश की सुरक्षा और गरिमा को कठिनाई में डालने वाला होगा। हालांकि सरकार भरोसा दे रही है कि वह संसद में पारित परमाणु दायित्व कानून से इतर कोई समझौता नहीं करेगी, लेकिन परमाणु दायित्व कानून की धारा 17 पर जिस तरह अटार्नी जनरल जीई वाहनवती ने अपना एकांगी दृष्टिकोण पेश कर सरकार की मंशा जाहिर की है, उससे साफ हो जाता है कि सरकार ने परमाणु तकनीक प्रदान करने वाली अमेरिकी कंपनियों को रियायत देने का मन बना लिया है।

अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो फिर ये अमेरिकी कंपनियां परमाणु जिम्मेदारी वाले उस कानून के दायरे से मुक्त होंगी, जो उन्हें दुर्घटना की स्थिति में दंड का भागीदार बनाता है और मुआवजा देने को बाध्य करता है। परमाणु दायित्व कानून की धारा 17 में स्पष्ट उल्लेख है कि परमाणु बिजली घरों में लगाए गए रिएक्टरों में अगर खराबी के कारण दुर्घटना होती है तो इसके लिए सप्लायर कंपनियां जिम्मेदार होंगी। वेस्टिंगहाउस और जीइ जैसी अमेरिकी कंपनियों ने इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल रखा हैं। दरअसल, उन्हें लग रहा है कि इस कानून के चलते उनके उत्पादों के बीमा का खर्चा बढ़ जाएगा और वे मनमाफिक मुनाफा हासिल नहीं कर सकेंगी।

वेस्टिंगहाउस कंपनी जो गुजरात के मिठीविर्दी में एक हजार मेगावाट के छह परमाणु बिजलीघर लगाने की योजना पर काम कर रही है, वह चाहती है कि अंतिम समझौता से पहले भारतीय संसद में पारित परमाणु दायित्व कानून उस पर न थोपा जाए। गौरतलब है कि इस नाभिकीय संयंत्र के लिए भारत को 1 करोड़ 51 लाख 60 हजार डॉलर खर्च करने होंगे। अमेरिका चाहता है कि भारत परमाणु दायित्व कानून की धारा 17 पर नरमी बरते। वह अपनी कंपनियों के हितों को ध्यान में रख पहले भी राग अलाप चुका है कि परमाणु रिएक्टर बेचने की दिशा में परमाणु दायित्व कानून अवरोध है। बता दें कि 2008 में हुए भारत–अमेरिका नाभिकीय सहयोग समझौते के बाद अभी तक दोनों देशों के बीच खरीद का सौदा नहीं हो सका है।

दरअसल, अमेरिकी कंपनियां 2010 में भारत की संसद में पारित नाभिकीय उत्तरदायित्व कानून से डर रही हैं। यह कानून विदेशी आपूर्तिकर्ता की जवाबदेही तय करता है। अमेरिका से परमाणु करार के दौरान संप्रग सरकार ने दावा किया था कि इस समझौते से भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन सच्चाई है कि पांच साल बाद भी भारत के कई परमाणु रिएक्टर आवश्यक ऊर्जा तथा नवीन टेक्नोलॉजी की अनुपलब्धता के चलते बंद पड़े हैं। अब जब सरकार के कार्यकाल के गिने–चुने दिन रह गए हैं, ऐसे में परमाणु

ऊर्जा मंत्रालय की मानें तो देश में तकरीबन छह हजार स्थानों पर लघु पनबिजली परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं। इसी तरह सौर ऊर्जा से पांच हजार खरब यूनिट बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन विडंबना है कि केंद्र की संप्रग सरकार इस दिशा में ठोस पहल करने के बजाय परमाणु रिएक्टरों को ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत मान इसे हासिल करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने से हिचक नहीं रही है।

करार पर उसकी हड़बड़ी कई तरह का सवाल खड़ा करती है। समझ से परे है कि वे कौन से कारण हैं, जिसकी वजह से वह अमेरिका के आगे बिछी जा रही है।

सरकार को देश को बताना चाहिए कि वह अमेरिकी कंपनियों को उन्हीं की शर्तों पर नाभिकीय रिएक्टर लगाने की छूट क्यों देना चाहती है? देश को इससे क्या लाभ होगा? अगर सरकार की मंशा साफ है तो फिर वेस्टिंगहाउस कंपनी को भारतीय कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए कैबिनेट मसौदा तैयार क्यों किया गया? इस मसौदे में यह प्रावधान क्यों रखा गया कि परमाणु बिजलीघर चलाने वाली भारतीय कंपनी नाभिकीय ऊर्जा निगम (एनपीसीआइएल) की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह दुर्घटना की हालत में रिएक्टर सप्लाई करने वाली कंपनी पर जिम्मेदारी डाले या नहीं?

सवाल यह भी कि इस मसौदे को परमाणु ऊर्जा आयोग की सलाह के बिना ही तैयार क्यों किया गया? सरकार के पास इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। सवाल सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है। सच यह भी है कि इस परियोजना पर अधिक लागत आएगी और बिजली महंगी होगी। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस महंगी बिजली का खरीददार कौन होगा? यह तथ्य है कि मिठीविर्दी में लगने वाले रिएक्टर पर 1 मेगावाट बिजली के उत्पादन पर तकरीबन 40 करोड़ रुपये खर्च आएगा। यानी रिएक्टर की प्रतिवाट कीमत 12 रुपये से अधिक होगी। जबकि दूसरी ओर कुडनकुलम में लगने वाले तीसरे और चौथे रिएक्टरों पर 1 मेगावाट बिजली के उत्पादन पर तकरीबन 22 करोड़ रुपये खर्च आएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की दलील है कि इसकी लागत और बिजली पैदा करने की कीमत का दूसरे ऊर्जा स्रोतों से तुलनात्मक अध्ययन होगा और फिर रूस, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से लगने वाले सभी प्रोजेक्टों पर समान रूप से लागू होगा। लेकिन यह दलील संतोषजनक नहीं है।

सरकार के रवैये से ऐसा लगता है कि वह मान बैठी है कि इन कंपनियों को रियायत नहीं दी गई तो वे भारत से मुंह मोड़ लेंगी। सच यह है कि भारत परमाणु बिजली घरों का विशाल बाजार बन चुका है और कोई भी विदेशी कंपनी खुद को इस बाजार अलग नहीं रख सकती। रूस और फ्रांस के मैदान में होने से प्रतिद्वंद्विता बढ़नी तय है। बेहतर होता कि सरकार इसका अधिकाधिक लाभ उठाती। लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से भारतीय हितों को किनारे रख विदेशी कंपनियों पर मेहरबान दिख रही है।

सवाल सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है। सच यह भी है कि इस परियोजना पर अधिक लागत आएगी और बिजली महंगी होगी। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस महंगी बिजली का खरीददार कौन होगा?

सरकार को समझना होगा कि परमाणु दायित्व कानून की धारा 17 पर झुक कर समझौता करने से देश की सुरक्षा प्रभावित होगी। जानमाल के खतरे बढ़ेंगे। दशकों पहले भोपाल गैस कांड की त्रसदी देश भुगत चुका है। हादसे में जान गंवा चुके लोगों के परिजन आज भी मुआवजे से वंचित हैं। 25 साल पहले यूक्रेन में हुए चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसे से भी सरकार को सबक लेने की जरूरत है। इस दुर्घटना के बाद यूरोप में एक भी नया परमाणु रिएक्टर नहीं लगा है। पुराने रिएक्टर ही मुसीबत बने हुए हैं। जापान का फुकुशिमा रिएक्टर तबाही के कगार पर है। यह रिएक्टर अमेरिकी डिजाइन का है।

भारत खुद भी परमाणु दुर्घटना का शिकार हुआ है। 1987 में तमिलनाडु के कलपक्कम रिएक्टर का हादसा, 1989 में तारापुर में रेडियोधर्मी आयोडीन का रिसाव, 1993 के नरौरा के रिएक्टर में आग, 1994 में कैगा रिएक्टर से विकिरण किसी से छिपा नहीं है। उचित होगा कि सरकार परमाणु दायित्व पर हड़बड़ी दिखाने के बजाय स्वदेशी और विदेशी परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा और जवाबदेही पर ध्यान टिकाए। यह सच है कि ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति और आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल के लिए भारत को अमेरिका तथा अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के साथ तालमेल रखना जरूरी है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि सरकार परमाणु रिएक्टर हासिल करने के लिए राष्ट्रीय हितों को ही ताक पर रख दे। परमाणु रिएक्टर ऊर्जा के एकमात्र स्रोत नहीं हैं। अन्य स्नोतों से भी ऊर्जा हासिल की जा सकती है। पवन ऊर्जा में अपार संभावनाएं हैं। मसलन, अकेले पवन उर्जा से ही 48,500 मेगावाट बिजली उत्पादित की सकती है।

ऊर्जा मंत्रालय की मानें तो देश में तकरीबन छह हजार स्थानों पर लघु पनबिजली परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं। इसी तरह सौर ऊर्जा से पांच हजार खरब यूनिट बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन विडंबना है कि केंद्र की संप्रग सरकार इस दिशा में ठोस पहल करने के बजाय परमाणु रिएक्टरों को ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत मान इसे हासिल करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने से हिचक नहीं रही है। ❑

भूलना मत कि एक मां गंगा भी है

गरीब से गरीब आदमी आज भी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च कर गंगा दर्शन को आता है लेकिन गंगा का रुदन और कष्ट हमें दिखाई नहीं देता। हमारे कान गंगा का रुदन सुनने में असमर्थ ही रहते हैं। गंगा के साथ मां का हमारा संबोध झूठा है। हर हर गंगे! की तान दिखावटी है। प्राणविहिन दरअसल हमने गंगा को अपनी मां नहीं, अपनी लालच की पूर्ति का साधन समझ लिया है; भोग का एक भौतिक सामान मात्र! मां को कूड़ादान मानकर हम मां के गर्भ में अपना मूल–मूत्र, कचरा–विष सब कुछ डाल रहे हैं।

■ अरुण तिवारी

नवरात्र! यद्यपि ये नौ दिन आदि मातृषक्तियों की पूजा की रातों को अपने साथ लेकर आते हैं और मां गंगा आदि शक्ति नहीं है; यह बाद में धरती पर अवतरित हुई; फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसी मां गंगा है, वैसी दुनिया में कोई और नहीं। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी मां है, जिसे धरा पर उतारकर एक इंसान ने स्वयं को उसकी संतान कहलाने योग्य साबित किया। भारत में भी ऐसी कोई दूसरी नदी या मां हो तो बताइए? मैं अक्सर सोचा करता हूं कि आखिर गंगा के ममत्व में कोई तो बात है कि कांवरिये गंगा को अपने कंधों पर सवार कर वहां भी ले जाते हैं, जहां गंगा का कोई प्रवाह नहीं जाता। आप पूछ सकते है कि आखिर इस मां में ऐसा क्या है कि गंगा अनषनरत़ प्रो. जीडी अग्रवाल जैसे आईआईटी, कानपुर का प्रोफेसर विज्ञानी भी कह रहा है – गंगा मेरी मां है। मैं मां के प्राणों की कीमत पर अपनी प्राणरक्षा नहीं करना चाहता।

मेरे गांव का रमाकांत का मन जब बेचैन होता है या उसे अपनी किसी समस्या का समाधान सुझाए नहीं सूझता, वह अपनी मां के पास नहीं जाता। वह उस मां के पास जाता है, जिसे उसकी मां भी मां कहती है – गंगा मां! व्ह कहता है कि गंगा के प्रथम स्पर्ष के साथ ही वह शांत होने लगता है, उसकी बेचैनी मिट जाती है। वह कहता है कि गंगा मां ने उसे कभी अनुत्तरित नहीं लौटाया।

ये इस 21वीं सदी के दूसरे दषक के लौकिक जगत के सच्चे अनुभव हैं। ''मैं तोहका सुमिरौ गंगा माई'' और ''गंगा मैया तोहका पियरी चढइबै'' जैसे गीत गंगा के मातृत्व के प्रति लोकास्था के गवाह हैं ही। *''अल्लाह मोरे अइहै, मुहमम्द मोरे अइहै। आगे गंगा थामला, यमुना हिलोरे लेयं। बीच मा खड़ी बीबी फातिमा, उम्मत बलैया लेय. . . दूल्हा बने रसूल।''* इन पंक्तियों को पढ़कर भला कौन नकार सकता है कि गंगा के ममत्व का महत्व सिर्फ हिन्दुओं के लिए नहीं, समूचे हिन्दोस्तान के लिए है।

गंगा का एक परिचय वराह पुराण में उल्लिखित षिव की उपपत्नी और स्कन्द कार्तिकेय की माता के रूप में है। दूसरा परिचय राजा शान्तनु की पत्नी और एक ऐसी मां के रूप में है, जिसने पूर्व कर्मों के कारण शापित अपने पुत्रों को तारने के लिए आठ में सात को जन्म देने के बाद तुरंत खुद ही मार दिया। पिता राजा शान्तनु मे मोह और पूर्व जन्म के शाप के कारण जीवित बचे आठवें पुत्र को आज हम गंगादत्त, गांगेय, देवव्रत, भीष्म के नाम से जानते हैं।

वाल्मीकि कृत गंगाष्टम, स्कन्दपुराण, विष्णुपुराण, ब्रह्मपुराण, अग्नि पुराण, भागवत पुराण, वेद, गंगा स्तुति, गंगा चालीस, गंगा आरती और रामचरितमानास से लेकर जगन्नाथ की गंगालहरी तक. . .मैंने जहां भी खंगाला, गंगा का उल्लेख उन्हीं गुणों के साथ मिला, वे सिर्फ एक मां में ही संभव है, किसी अन्य में नहीं। त्याग और ममत्व! सिर्फ देना ही देना, लेने की कोई अपेक्षा नहीं। शायद इसएि मां को सबसे तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है और गंगा को भी।

संत रैदास, रामानुज, वल्लभाचार्य, रामानन्द, चैतन्य महाप्रभु सभी ने गंगा के मातृस्वरूप को भी प्रथम मान महिमागान गाये। महाबलीपुरम्, अमरावती, उदयगिरि, देवगढ़, भीतरगांव, दहपरबतिया, पहाड़पुर, जागेष्वर, बोधगया, हुगली, महानद से लेकर भेड़ाघाट के चौंसठ योगिनी मंदिर आदि कितने ही स्थानों में गया। इनमें स्ाापित गुप्तकालीन, शुंगकालीन, पालकालीन और पूर्व मध्यकालीन इतिहास प्रतिमाओं में कितनी ही प्रतिमायें गंगा की पाई। कहीं यक्षिणी, तो कहीं देवी प्रतिमा के रूप में स्थापित इन गंगा मूर्तियों में मातृत्व भाव ही परिलक्षित होता है कोई और भाव जगता ही नहीं।

इसी विष्वास को लेकर वर्ष 2011 में मैंने सोचा कि गंगा के मातृत्व को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, तभी गंगा का मातृत्व सुरक्षित रह सकेगा; तभी हम संतानों को गंगा के साथ मां जैसे व्यवहार के लिए बाध्य कर सकेंगे। जब मैंने पहली बार यह मांग दिल्ली की एक बैठक में रखी, तो सरकारी अमले के नकारने से पहले एक छात्र ने ही इसे नकार दिया। मैं अवाक रह गया। मुझसे कुछ उत्तर देते न बना। उसने कहा ''गंगा में ऐसा क्या है? मांग का समर्थन करना तो दूर, मुझे तो इसे मां कहने में भी शर्म आएगी।'' फिर मैंने

यही सवाल मुंबई में दादा की एक पोती से पूछा। वह गंगा माई को उसके घर में काम करने वाली महरी समझ बैठी। मैं सन्न रह गया। ऐसे एक क्यूं ने मेरे में सैकड़ों क्यूं खड़े कर दिए। मेरे यह जानना, समझना और समझाना जरूरी हो गया कि मेरी संतानें गंगा को मां क्यूं कहे।

तर्क मिले। लहलहाते खेत माल से लदे जहाज और मेले ही नहीं, बुद्ध–महावीर के विहार, अषोक–अबकर–हर्ष जैसे सम्राटों के गौरव पल. . .तुलसी, कबीर, नानक की गुरुवाणी भी इसी गंगा की गोद में पुष्पित पल्लवित हुई है। इसी गंगा के किनारे में तुलसी का रामचरित, आदिगुरु शंकराचार्य का गंगाष्टक और पांच श्लोकों में लिखा जीवन सार – मनीषा पंचगम, जगन्नाथ की गंगालहरी, कर्नाटक संगीत के स्थापना पुरुष मुत्तुस्वामी दीक्षित का राग झंझूती, कौटिल्य का अर्थषास्त्र, टैगोर की गीतांजलि और प्रेमचंद के भीतर छिपकर बैठे उपन्यास सम्राट ने जन्म लिया। शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की तान यहीं परवान चढ़ी। आचार्य वाग्भट्ट ने गंगा के किनारे बैठकर ही एक हकीम से तालीम पाई और आयुर्वेद की 12 शाखाओं का विकास किया। कौन नहीं जानता कि नरोरा के राजघाट पर महर्षि दयानन्द के चिंतन ने समाज को एक नूतन आलोक दिया! नालन्दा, तक्षषिला, काषी, प्रयाग अतीत के सिरमौर रहे चारों षिक्षा केन्द्र गंगामृत पीकर ही लंबे समय तक गौरवषाली बने रह सके। आर्यभट्ट के जमाने में आर्थिक और कालांतर में जैन तथा बौद्ध दोनों आस्थाओं के विकास का मुख्य केन्द्र रहा पाटलिपुत्र! भारतवर्ष के अतीत से लेकर वर्तमान तक एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं, जिसे गंगा ने सिंचित न किया हो। भारत विभाजन का अगाध कष्ट समेटने महात्मा गांधी भी हुगली के नूतन नामकरण वाली गंगा–सागर संगम पर ही गए – नोआखाली।

लेकिन भारत के लिए गंगा के ये सभी योगदान उस नौजवान और दादा की उस पोती के सवाल के उत्तर के रूप में मुझे संतुष्ट नहीं कर सके। असल उत्तर मुझे अतीत के पन्नों में ही मिला –

''यथा माता स्वयं जन्म मलषौच कारयेत्।
कोडीकृत्य तथा तेषां गंगाप्रक्षालयेन्मलम।।''

अर्थात् जिस प्रकार से माता स्वयं बच्चे को जन्म देती है, उसके मूल–मूत्र को साफ करती है, उसे गोदी में बिठाती है, उसी प्रकार गंगा भी. . . मनुष्य कैसा भी नीच या पापी क्यों न हो, उसके मल–मैल की प्रक्षालित कर उसे पवित्र बना देती है। पद्मपुराण के दस श्लोक की तरह गंगालहरी भी गंगा को एक ऐसी मां के रूप में उल्लिखित करती है जो ऐसे कुपूत को भी देखना चाहती है, जो कुत्ते की वृति धारण किए है, झूठ बोलता है, बुरी–बुरी कल्पनाएं करता है, दूसरे की बुराई में संलग्न है और जिसका मुख कोई दूसरा देखना नहीं चाहता – *''ष्ववृक्रिव्यासंगो नियतमथ मिथ्याप्रलपनं. . . नृते त्वत्को नामक्षणि मपि निरीक्षेत वदनम्।''*

इन दो उत्तरों को आज हम सच होते देख रहे हैं। आज हम गंगा को मां कहते जरूर हैं लेकिन हमारा व्यवहार एक संतान की तरह नहीं है। गरीब से गरीब आदमी आज भी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च कर गंगा दर्षन को आता है लेकिन गंगा का रुदन और कष्ट हमें दिखाई नहीं देता। हमारे कान गंगा का रुदन सुनने में असमर्थ ही रहते हैं। गंगा के साथ मां का हमारा संबोध झूठा है। हर हर गंगे! की तान दिखावटी है। प्राणविहिन दरअसल हमने गंगा को अपनी मां नहीं, अपनी लालच की पूर्ति का साधन समझ लिया है; भोग का एक भौतिक सामान मात्र! मां को कूड़ादान मानकर हम मां के गर्भ में अपना मूल–मूत्र, कचरा–विष सब कुछ डाल रहे हैं। अपने लालच के लिए हम मां को कैद करने से भी नहीं चूक रहे। हम उसकी गति को बांध रहे हैं। मां के सीने पर बस्तियां बसा रहे हैं। अपने लालच के लिए हम मां गंगा के गंगत्व को नष्ट करने पर उतारू हैं। हम भूल गए हैं कि एक संतान को मां से उतना ही लेने का हक है जितना एक षिषु को अपने जीवन के लिए मां के स्तनों से दुग्धपान।

हम यह भी भूल गए हैं कि मां से संतान का संबंध लाड, दुलार, स्नेह, सत्कार और संवेदनषील व्यवहार का होता है, व्यापार का नहीं। हमें गंगा मिलन के मेले याद है; स्नान और दीपदान याद हैं, लेकिन हम इन आयोजनों के मूल मंतव्य और गंगा अंतर्संबंध को भूल गए हैं।

जानाबूझ कर की जा रही हमारी इन तमाम गलतियों के कारण मां गंगा गुस्साती जरूर है, लेकिन वह आज भी भारत के 37 प्रतिषत आबादी का प्राणाधार बनी हुई है। आज भी मां गंगा भारत की कुल सिंचित भूमि के 47 प्रतिषत खेतों को पानी पिलाकर जिंदा रखती है। आज भी गंगा भारत के पानी और पर्यावरण का मॉनीटर बनी हुई है। गंगा एक ऐसी मां है जो खुद पर हो रहे तमाम अत्याचारों के बावजूद मृत्यु पूर्व दो बूंद जल की हमारी कामना की पूर्त्ति करने के लिए आज भी प्रस्तुत है।

दुनिया में नदियां बहुत हैं और मां भी बहुत। लेकिन गंगा जैसी कोई नहीं। क्या हम यह भूल जाएं? क्या ऐसी मां के मातृत्व की रक्षा हमारा दायित्व नहीं? क्या ऐसी मां को आज हम मां मानने से इनकार कर दें? क्या उस नौजवान और दादा की उस पोती के लिए इस पर कोई बहस संभव है? लेकिन जो बहस संभव है, उसे मैं उसी सवाल के रूप में आज आपके सामने रख रहा हूं, जो मां गंगा ने अपने अवतरण से पूर्व भगीरथ से पूछा था ''मैं इस कारण भी पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझमें अपने पाप धोयेंगे। हे पुत्र! बताओ, तब मैं अपने पाप धोने कहां जाऊंगी?'' सोचिए और मुझे भी बताइए। ❑

इंटरनेट की दुनिया में हमारी हिन्दी...?

हर साल हिंदी को आगे लाने को लेकर सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर हिंदी को स्थापित करने के लिए संकल्प किए जाते रहे। पर हिंदी की हालत देखिए कि मोबाइल और कंप्यूटर के बादशाह देश भारत में हिंदी अब भी कोने में पड़ी है। हम हिंदीभाषियों को अगर अपनी हिंदी पर गर्व है, तो हमें चाहिए कि इंटरनेट–फेसबुक पर हिंदी में लिखें और पढ़ें, तभी अपनी भाषा को बचा पाएंगे।

■ उमेश चतुर्वेदी

अटल बिहारी वाजपेयी ने जब भारत में संचार क्रांति यानी सेलुलर फोन क्रांति के एक बड़े वाहक भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल फोन का 2003 में लखनऊ में उद्घाटन किया था, तो उसे पंडोरा बॉक्स यानी जादुई बक्सा कहा था। इस जादुई बक्से, लैपटॉप और कंप्यूटरों के जरिये हमारे देश में इंटरनेट का बोलबाला बढ़ा है। पिछले महीने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 14 करोड़ 32 लाख इंटरनेट कनेक्शन हो गए हैं। यह संख्या बहुत बड़ी है। इंटरनेट का बढ़ता चलन ही है कि हमारे यहां यह मानने वाले भी बहुत ज्यादा हो गए हैं कि इंटरनेट के जरिये हिंदी का विस्तार हो रहा है। अव्वल तो होना यह चाहिए था कि इंटरनेटी विस्तार के दौर में हिंदी का भी विस्तार होता, क्योंकि चीन के बाद अगर सबसे ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता कहीं हैं, तो वे हमारे देश में ही हैं। इस हिसाब से तो हिंदी और मंदारिन का इंटरनेट पर विस्तार होना चाहिए था, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। कुछ दिनों पहले 'डब्ल्यू थ्री टेक्स' नामक अनुसंधान एजेंसी ने इंटरनेट पर हिंदी को लेकर जो आंकड़े दिए थे, वे कुछ और ही कहानी कह रहे हैं।

डब्ल्यू थ्री टेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट में अंग्रेजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट पर लिखी जाने वाली कुल इबारतों की 54.7 प्रतिशत अंग्रेजी में ही लिखी जाती हैं। दूसरे नंबर पर रूसी का स्थान आता है, जबकि तीसरे नंबर पर जर्मन भाषा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट पर उपयोग की जाने वाली शीर्ष 10 भाषाओं में हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा नहीं है।

सवा अरब से अधिक लोगों के बीच लोकप्रिय चीनी भाषा इंटरनेट पर उपयोग में लाई जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा होने के बावजूद हिंदी का स्थान अगर इस सूची में नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि इंटरनेट पर हमारी हिंदी के लोग भी अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करते हैं। इस सूची में अरबी, कोरियाई और जापानी जैसी भाषाओं का स्थान बना लेना मामूली बात नहीं है। आखिर रूसी दूसरे नंबर पर क्यों है? इसका जवाब विश्लेषकों ने दिया है। उनका कहना है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भी सोवियत संघ से अलग हुए कुछ देशों में रूसी भाषा प्रमुख भाषा बनी हुई है। उक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के डोमेन क्षेत्रों में भी रूसी भाषा ही प्रमुख है। जानकारों का कहना है कि अभी कई बरस तक इंटरनेट में रूसी भाषा दूसरे नंबर पर बनी रहेगी।

चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया रिसर्च के शोधार्थी लियू रुईशेंग ने बताया कि वर्ष 2000 में चीन में करीब 2.25 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग किया करते थे। उस समय इंटरनेट का उपयोग करने वाले प्रति 100 लोगों में चीनी लोगों की संख्या विकासशील देशों के औसत से भी कम थी। साल 2010 में चीन में इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 34 फीसदी तक पहुंच गई। ये संख्या विकासशील देशों में इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों के औसत से डेढ़ गुना ज्यादा है।

जिस तरह चीन में मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या दूसरे विकासशील देशों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, उसी तरह यहां इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। चीन में अभी 90 करोड़ लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। इसकी तुलना में अपनी हिंदी वालों को देखिए। यहां हिंदी का इस्तेमाल करने के बजाय लोगों को अंग्रेजी में ही काम करने और इंटरनेट पर इस्तेमाल करने की ललक ज्यादा है। तथ्य यह भी है कि हमारे यहां अब भी औपनिवेशिक मानसिकता हावी है। 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना शुरू किया था। तब से लेकर हर साल हिंदी को आगे लाने को लेकर सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर हिंदी को स्थापित करने के लिए संकल्प किए जाते रहे। पर हिंदी की हालत देखिए कि मोबाइल और कंप्यूटर के बादशाह देश भारत में हिंदी अब भी कोने में पड़ी है। हम हिंदीभाषियों को अगर अपनी हिंदी पर गर्व है, तो हमें चाहिए कि इंटरनेट–फेसबुक पर हिंदी में लिखें और पढ़ें, तभी अपनी भाषा को बचा पाएंगे। ❑

रपट

चीनी षड़यंत्र के विरुद्ध स्वदेशी अभियान

चीन न सिर्फ सामरिक रूप से, बल्कि आर्थिक संप्रभुत्ता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। चीन दैनिक उपयोग की लगभग प्रत्येक घटिया वस्तु को भारतीय बाजारों में सस्ते दामों में पहुंचाकर स्थानीय उद्योग को लगभग बंद करने की स्थिति में पहुंचा दिया है। केंद्र की सरकार देश की संप्रभुत्ता की रक्षा करने में विफल रही है। स्वदेशी जागरण मंच काशी प्रान्त में एक लाख से अधिक युवाओं को चीनी साजिश के खिलाफ आगाह करेगा।

– डॉ. निरंजन सिंह

दिनांक 7 अक्तूबर के दिन चीन की भारत विरोधी आर्थिक और सामरिक नीतियों के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत इलाहबाद में युवाओं के बीच जागरूकता अभियान की शुरुआत की गयी। इलाहबाद विश्वविद्यालय में विधि विभाग के प्रोफेसर डा. जयशंकर सिंह ने पी.सी.बी. छात्रावास से अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि चीन कभी भी भारत का मित्र नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वह पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा कर रहा है।

प्रोफेसर सिंह ने कहा कि हिंदी चीनी भाई–भाई का नेहरू का नारा एक ऐतिहासिक भूल थी। क्योंकि इतिहास गवाह है कि वह कभी किसी पड़ोसी से दोस्ती नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारा नेतृत्व कमजोर है जिसका फायदा उठाकर वह हमेशा आँखें दिखाता रहता है। स्वदेशी जागरण मंच का यह अभियान युवाओं में राष्ट्र के प्रति सजगता के लिए सकारात्मक है।

काशी प्रांत के संयोजक डॉ. निरंजन सिंह ने कहा कि चीन न सिर्फ सामरिक रूप से, बल्कि आर्थिक संप्रभुत्ता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। चीन दैनिक उपयोग की लगभग प्रत्येक घटिया वस्तु को भारतीय बाजारों में सस्ते दामों में पहुंचाकर स्थानीय उद्योग को लगभग बंद करने की स्थिति में पहुंचा दिया है। चीन द्वारा जम्मू कश्मीर को अपने नक्शे में भारत का अंग नहीं दिखाया जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश को चीन का अंग दिखाकर वहां के नागरिकों को बिना पासपोर्ट वीसा के अपने देश आने का निमंत्रण दिया जाता है।

डॉ. सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार देश की संप्रभुत्ता की रक्षा करने में विफल रही है। स्वदेशी जागरण मंच काशी प्रान्त में एक लाख से अधिक युवाओं को चीनी साजिश के खिलाफ आगाह करेगा।

उन्होने कहा कि अगले एक माह तक पूर्वांचल के सभी जिलों में पत्रक के माध्यम से आम आदमी, युवाओं और छात्रों के बीच चीनी साजिश का भंडाफोड़ किया जाएगा। जिला संयोजक सुरेश बहादुर सिंह ने चीनी षड़यंत्र को पर्दाफाश करने वाले स्वदेशी जागरण मंच के पत्रक को छात्रों को पढ़कर सुनाया और कहा कि आज युवाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है।

अभियान के संयोजक और विचार मंडल प्रमुख डॉ. विजय कुमार सिंह ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि चीन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसे नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होने बताया कि अभियान की कड़ी में डायमंड जुबिली छात्रावास में युवाओं को जागरूक किया जाएगा।

पी.सी.बी. के कामन हाल में आयोजित अभियान के शुभारंभ पर कौशाम्बी के जिला संयोजक हरिओम नारायण पांडे, केशव सिंह आजाद सिंह, अजित कुमार श्रीवास्तव, छात्रावास के अन्तःवासी विपिन मिश्र, दिनेश कुमार गर्ग, राम प्रताप सिंह, विनय भदौरिया एवं मुकेश तिवारी अनेक कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। ❑

चीन व पाकिस्तान का हो बहिष्कार

जमशेदपुर : बीते दिनों स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाए जा रहे 'राष्ट्र सुरक्षा अभियान'' के तहत वीमेंस कॉलेज (जमशेदपुर) में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वीमेन्स कॉलेज की प्राचार्य डॉ. सुमिता मुखर्जी ने कहा हमें चीन, पाकिस्तान समेत भारत विरोधी देशों का सभी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। ऐसा कर हम अपने देश व समाज की सुरक्षा के साथ बेहतर ढंग से उन्नति भी कर सकेंगे। मंच के राष्ट्रीय परिषद सदस्य मनोज कुमार सिंह ने कहा कि चीन का विरोध हम उनके सामान का बहिष्कार कर करें। कार्यक्रम का संचालन परिषद के राकेश पाण्डेय ने किया और धन्यवाद ज्ञापन नवनीत कुमार ने किया। इस मौके पर कॉलेज की बीएड छात्राएं व फैकल्टी उपस्थित थे। ❑

चीन के उत्पाद का करें बहिष्कार

पाक अधिकृत जम्मू–कश्मीर, नेपाल, बांग्लादेश व श्रीलंका में चीन सेना की उपस्थिति भारत के लिए खतरा है, हम सबको चीनी उत्पादन का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। – कश्मीरीलाल जी

25 सितम्बर (जबलपुर)। हम चीन का आर्थिक सशक्तिकरण बंद करें, चीन का आर्थिक एवं सामरिक बढ़त में आज एक बड़ा योगदान हम भारतीयों का भी है। स्वदेशी जागरण मंच (जबलपुर) द्वारा गढ़ा में आयोजित ''चीन की चुनौती एवं समाधान'' विषय के कार्यक्रम में नीलकंठ पैंठसे ने कहीं।

प्रदेश सह संयोजक डी.के. विश्वकर्मा ने कहा कि चीन से भारत को आर्थिक एवं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। मुख्यवक्ता अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल जी ने कहा पाक अधिकृत जम्मू–कश्मीर, नेपाल, बांग्लादेश व श्रीलंका में चीनी सेना की उपस्थिति भारत के लिए खतरा है, हम सबको चीनी उत्पादन का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए।

कार्यक्रम में अतिथि परिचय आलोक मिश्रा ने दिया। संचालन लोकराम कोरी, स्वागत सुरेन्द्र राठौर, अवधेश श्रीवास्तव, कार्यक्रम में नरेन्द्र कोष्ठी, प्रशांत तिवारी, पंजक नेगा, राजेश ठाकुर, निशांत बाजपेई, रजनीश त्रिपाठी, दीपक ठाकुर, मनोज ठाकुर, प्रदीप झरिया, दिलीप हजारी, अल्केश चतुर्वेदी, अमित कोरी, रत्नेश यादव, कमलेश यादव, सुरेश द्विवेदी, पवन बावरिया और अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। ❑

विदेशी वस्तु का करें बहिष्कार

स्वदेशी जागरण मंच (जमशेदपुर) गम्हरिया प्रखंड इकाई की ओर से राष्ट्र सुरक्षा अभियान के तहत गम्हरिया व कांड्रा में जन जागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान मंच द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन कर लोगों से चीन व अन्य देशों में निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तु अपनाने की अपील की गई। मंच के जिला संयोजक जगदेव सिंह ने कहा कि चीन में निर्मित वस्तुएं सस्ता हैं लेकिन इससे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है। कोल्हन प्रमंडल के अभियान संयोजक डॉ. अनिल राय ने कहा कि विदेशी वस्तुओं के प्रयोग के कारण देश के उद्योग–धंधे बंद हो रहे हैं। इसका कुप्रभाव आम लोगों पर पड़ रहा है।

सभा का संचालन प्रखंड संयोजक रमेश कुमार ने किया। इस मौके पर विजय श्रीवास्तव, कृष्ण मोहन राय, प्रमोद पाठक, अनिल सिंह, रामजस तिवारी, अश्विनी शुक्ला, बंदे शंकर, प्रभात मंडल और राहुल सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता व आमजन उपस्थित थे। ❑

चीनी सामान की जलाई होलिका

स्वदेशी जागरण मंच (जमशेदपुर) के तत्वावधान में ''राष्ट्र सुरक्षा अभियान'' के तहत गणेश पूजा मैदान में चीन निर्मित वस्तुओं के दहन का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सरयू राय ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने की बात कही। विशिष्ट अतिथि के रूप में अनिल ठाकुर आरएसएस व स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल, बंदेशंकर सिंह व मनोज सिंह ने अपने विचार रखे।